



हिंदुत्व का आधार नफरत नहीं, लोगों को जोड़ना: मोहन भागवत

नईदिल्ली। ब्रिटेन के लंदन में एकता का जश्न कार्यक्रम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। उन्होंने हिंदुत्व, सेवा और समाज के भविष्य पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने संघ की सोच का आधार शुद्ध सात्त्विक प्रेम और अपनापन बताया। भागवत ने कहा कि हिंदू सोच में परिवार, समाज, मानवता और प्रकृति एक-दूसरे से जुड़े हैं।

लंदन में आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत एकता का जश्न कार्यक्रम में शामिल हुए। लंदन में आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत एकता का जश्न कार्यक्रम में शामिल हुए। आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत ब्रिटेन दौरे पर हैं। लंदन में रविवार को वे एकता का जश्न कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, सेवा और समाज के भविष्य पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संघ के काम का आधार नफरत नहीं है। इसके उलट इसका आधार शुद्ध सात्त्विक प्रेम है। समाज में लोगों को जोड़ना और सभी के प्रति

अपनापन रखना संघ की सोच का हिस्सा है। भागवत ने कहा कि अपनापन संघ को समझने की सबसे अहम कुंजी है। हिंदू की सोच में परिवार, समाज, मानवता और प्रकृति सभी एक-दूसरे से जुड़े हैं। हिंदू केवल पूजा करने वाला व्यक्ति नहीं है। वह प्रकृति से भी प्रेम करता है। इसलिए ईंसान की प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईंसान खुद प्रकृति का हिस्सा है।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विकास केवल व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। व्यक्ति, समाज, मानवता और प्रकृति सभी की एक साथ प्रगति जरूरी है। अगर केवल व्यक्ति को महत्व दिया गया तो समाज कमजोर होगा। अगर केवल समाज को महत्व दिया गया तो व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो सकती है। इसलिए दोनों के बीच संतुलन बना रहे ये बहुत जरूरी है।

उन्होंने कहा कि हिंदू विचार में दुनिया को एक इकाई के रूप में देखने की बात है। इसी वजह से अलग-अलग विचारों और विविधताओं को स्वीकार करने की भावना



पैदा होती है। विविधता स्वाभाविक है। लेकिन उसके पीछे एकता को देखना जरूरी है। उनका संदेश था कि जो बात लोगों को जोड़ती है, उस पर ज्यादा जोर होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व पर पूछे गए सवाल के जवाब में भागवत ने कहा कि हिंदू को केवल धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं समझा जा सकता। उन्होंने इसे एक प्रकृति

और सोच बताया। उनका कहना है कि भारत में नास्तिक से लेकर आस्तिक और अलग-अलग विचार रखने वाले लोग रहे हैं। हिंदू सोच का दावा है कि अलग-अलग रास्तों को स्वीकार किया जा सकता है।

भागवत ने राष्ट्र और 'नेशन' में भी अंतर बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक अर्थ में नेशन अक्सर एक राज्य और उसकी व्यवस्था

से जुड़ा होता है। लेकिन 'राष्ट्र' का आधार केवल शासन व्यवस्था नहीं है। इसके पीछे एक उद्देश्य और साझा चेतना होती है।

भागवत ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य दुनिया को यह बताना है कि विविधता स्वाभाविक है और एकता वास्तविकता है। भारत में राजाओं और शासन व्यवस्थाओं में बदलाव होते रहे। कभी गणराज्य रहे और कभी विदेशी शासन भी रहा। लेकिन भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना बनी रही। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति का मतलब किसी दूसरे देश के खिलाफ जाना नहीं है। बल्कि भारत आगे बढ़े तो उसका फायदा पूरी दुनिया को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति शांति, समृद्धि और मानवता के लिए होनी चाहिए। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं को लेकर भागवत ने कहा कि उनकी कर्मभूमि जहां है, उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। ब्रिटिश हिंदू ब्रिटेन के साथ जाएं और अपने देश के प्रति ईमानदार रहें। भारत से जुड़ाव रखने और ब्रिटेन के प्रति निष्ठावान रहने में कोई

विरोधाभास नहीं है। उन्होंने कहा कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली की भावना के साथ काम किया जा सकता है। अगर किसी के पास समय और साधन हैं तो वह भारत की सेवा कर सकता है। लेकिन इससे उसकी कर्मभूमि के प्रति जिम्मेदारी खत्म नहीं होती।

भागवत ने सेवा को भी संघ की सोच का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि सेवा किसी पर उपकार करना नहीं है। सेवा करने वाले को खुद इसे सौभाग्य समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छी सेवा वह है जिसमें जिसे मदद मिल रही है, वह आगे चलकर खुद दूसरों की मदद करने वाला बन जाए।

उन्होंने युवाओं पर भरोसा जताया। कहा कि नई पीढ़ी में दुनिया को बेहतर बनाने की इच्छा है। युवाओं को उद्देश्य देना चाहिए।अनुभव शेयर करना चाहिए। लेकिन उनके ऊपर अपने तरीके नहीं थोपने चाहिए। उन्हें अपना रास्ता खोजने का अवसर मिलना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां देश और दुनिया के लिए बेहतर काम कर सकती हैं।

छह सीटों पर उपचुनाव छह अक्टूबर को, नतीजे नौ अक्टूबर को

नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने सोमवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम में पांच विधानसभा एवं एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की।

इन सीटों पर छह अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना नौ अक्टूबर को होगी।

आयोग के अनुसार चुनाव संबंधी गजट अधिसूचना 9 सितंबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 19 सितंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान मंगलवार, छह अक्टूबर को और मतगणना



शुक्रवार, छह अक्टूबर को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 11 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।

तमिलनाडु में मदुरातकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। पुडुचेरी की थट्टनचावडी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होगा। वहीं, असम की नगांव लोकसभा सीट पर मतदान कराया जाएगा। इन सभी सीटों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के इस्तीफे

के कारण रिक्तियां हुई हैं। मदुरातकम सीट मारगाथम कुमारवेल के इस्तीफे के बाद, जबकि धारापुरम सीट पी. सत्यबामा के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई। पुडुचेरी की थट्टनचावडी सीट एन. रंगासामी के इस्तीफे के बाद खाली हुई। पश्चिम बंगाल में रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें क्रमशः हुमायूं कबीर और शुभेन्दु अधिकारी के इस्तीफे के बाद रिक्त हुईं। असम की नगांव लोकसभा सीट प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई।

आयोग ने कहा कि जिन जिलों में इन चुनाव क्षेत्रों का पूरा या कोई हिस्सा आता है, वहां तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

भारत-पाकिस्तान के बीच फिर से महासंग्राम!

नईदिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व मानचित्र को अधिक सटीक बनाने संबंधी प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर जोरदार कूटनीतिक भिड़ंत छिड़ गई है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसके संप्रभु क्षेत्र, जिनमें केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं, को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुरूप ही दिखाया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार का “गलत” या “भ्रामक” चित्रण स्वीकार्य नहीं होगा। वहीं पाकिस्तान ने इस स्पष्ट भारतीय रुख पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उसे “निराधार” बताया है।

हम आपको बता दें कि ताजा विवाद की पृष्ठभूमि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चार सितंबर को पारित उस प्रस्ताव से जुड़ी है, जिसका शीर्षक है— ‘क्रेकट द मैप:



वैश्विक मानचित्रण प्रतिनिधित्व में संतुलन और विश्व के क्षेत्रों, विशेषकर अफ्रीका का समान प्रतिनिधित्व।' टोगो द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव को 164 देशों का समर्थन मिला। अमेरिका ने इसके खिलाफ अकेले मतदान किया, जबकि एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, सर्बिया और यूक्रेन मतदान से दूर रहे।

इस प्रस्ताव का मूल उद्देश्य राजनीतिक सीमाओं को बदलना या किसी देश के

क्षेत्रीय दावों को मान्यता देना नहीं, बल्कि ऐसी ‘इक्वल एरिया’ मैप प्रोजेक्शन प्रणाली को प्रोत्साहित करना है, जिसमें महाद्वीपों और भूभागों का वास्तविक क्षेत्रफल अपेक्षाकृत सही अनुपात में दिखाई दे। दरअसल, अफ्रीकी देशों की लंबे समय से यह शिकायत रही है कि प्रचलित मानचित्र प्रक्षेपणों में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से छोटा दिखाई देता है। संयुक्त राष्ट्र की पहल सरकारों, स्कूलों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और तकनीकी कंपनियों को अधिक संतुलित मानचित्रण पद्धतियों, विशेषकर ‘इक्वल अर्थ’ जैसी प्रोजेक्शन प्रणालियों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करती है।

लेकिन भारत ने प्रस्ताव के समर्थन के साथ ही एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सुरक्षा-कवच भी खड़ा कर दिया है। विदेश

मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि भारत का समर्थन केवल भूभागों के वास्तविक आकार के अनुपात को बनाए रखने वाली मानचित्रण पद्धति के सिद्धांत के लिए है। भारत ने किसी विशेष नक्शे, प्रक्षेपण या राष्ट्रीय सीमाओं के किसी खास चित्रण का समर्थन नहीं किया है।

जायसवाल का संदेश बेहद स्पष्ट था कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित भारत के संप्रभु क्षेत्र भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुरूप ही प्रदर्शित किए जाने चाहिए। उन्होंने दो टूट कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर उसका रुख “स्पष्ट, सुसंगत और गैर-परक़्राम्य” है। दूसरे शब्दों में, नई वैश्विक मानचित्रण बहस को भारत अपनी सीमाओं या क्षेत्रीय स्थिति पर किसी नए विवाद का मंच नहीं बनने देगा।

दिल्ली सरकार ने डिटी कमिश्नर सहित 5 को किया सरखेंड

नईदिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार सुबह घटना स्थल का दौरा किया था। जिसके बाद उन्होंने बिल्डिंग मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने और घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सत्य निकेतन में इमारत ढहनेकी घटना में जान गंवाने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 7 हो गई। जबकि मलबे से अब तक 12 लोगों को निकाला जा चुका है।

इमारत रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे मरम्मत कार्य के दौरान ढह गई थी। पुलिस ने दक्षिण परिसर में हरि राम और अन्य पर गैर इरादतन हत्या, संरचना के रखरखाव में लापरवाही और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में मामला दर्ज किया था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने बताया, इमारत ढहने की घटना के बाद बचाव एजेंसियों ने अब तक मलबे से 12 लोगों को बाहर निकाला है, जबकि मलबे के नीचे फंसे लोगों की सटीक संख्या का अभी पता नहीं चल पाया है।

झारखंड सीआईडी ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार

रांची। झारखंड पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने राज्य में एक भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा 2024 में आयोजित ‘झारखंड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023’ में कथित अनियमितताओं के मामले में राज्य की जांच एजेंसी ने 18 अगस्त से अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीआईडी ने रविवार रात जारी एक बयान में बताया कि इस सिलसिले में पलामू जिले के डुमरी गांव के रहने वाले कुंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले, जांच एजेंसी ने 27 अगस्त को दो आरोपियों, 28 अगस्त को जेएसएससी-सीजीएल 2024 परीक्षा के चार सफल अभ्यर्थियों और 30 अगस्त को झारखंड के गिरिडीह जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। सीआईडी ने जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत में मामले के मुख्य आरोपी अभय तिवारी, उसकी पत्नी और भाई को भी गिरफ्तार किया।

टीएमसी सांसद नदीमुल हक के ठिकानों पर ईडी ने तलाशी ली

नईदिल्ली। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली, पश्चिम बंगाल और झारखंड में सात जगहों पर तुणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक से जुड़ी जगहों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई टीएमसी सांसद द्वारा प्रमोट किए गए उर्दू दैनिक अखबार-



ए-मशरिक के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई। 56 वर्षीय हक, जो एक पत्रकार और व्यवसायी भी हैं, उस कंपनी (अखबार-ए-मशरिक प्राइवेट लिमिटेड) के डायरेक्टर हैं जो अखबार-ए-मशरिक नाम का दैनिक अखबार निकालती है। ईडी के कोलकाता ज़ोनल ऑफिस की टीम ने कोलकाता, दिल्ली और रांची में सात जगहों पर तलाशी ली। कोलकाता में पार्क सर्कस के दरगाह रोड पर अखबार-ए-मशरिक के ऑफिस में तलाशी ली गई। ऑपरेशन के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों ने ऑफिस की बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। सुरक्षा के लिहाज से मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, ताकि तलाशी के दौरान कोई अंदर न आ सके और न ही बाहर जा सके।

तमिलनाडु विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा!

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा का सत्र सोमवार को हंगामेदार मोड़ के साथ शुरू हुआ। विपक्षी दल डीएमके के विधायकों ने राज्य में हाल ही में हुई हत्याओं और कथित तौर पर बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर जोरदार नारेबाजी की और तुरंत चर्चा की मांग की। सदन में हंगामे के बीच मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अपनी सरकार के रुख का बचाव करते हुए पुलिसिंग व्यवस्था पर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को जनता का रक्षक बनाना चाहिए, न कि कोई स्वतंत्र पावर सेंटर (सत्ता का केंद्र)।

उन्होंने कहा कि पुलिस बल को नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, न कि सत्ता का केंद्र बनना चाहिए। विजय ने जोर देकर कहा कि कानून सभी के लिए समान है और अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो। विधानसभा को संबोधित करते हुए, विजय ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस विभाग की भूमिका पर जोर दिया। छरूविजय ने कहा, मैं इस सदन में एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूँ।

डीजे के शोर के मुद्दे पर फडणवीस दुविधा में हैं : संजय राउत

मुंबई। शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने सोमवार को डीजे प्रतिबंध विवाद को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि फडणवीस इस मुद्दे पर बीच का रास्ता अपनाकर बैठे हैं और कार्रवाई करने में विफल रहे हैं, जबकि ध्वनि प्रदूषण को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राउत ने आरोप लगाया कि पुणे में मुंबई और नागपुर की तुलना में अलग रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुंबई और नागपुर में पुलिस प्रमुखों ने तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम पर पाबंदियां लागू कर दी हैं। उन्होंने कहा, लोग सड़कों पर उतरकर डीजे साउंड सिस्टम से होने वाली शारीरिक और मानसिक परेशानियों के बारे में अपनी बात रख रहे हैं। ये मुद्दे केवल पुणे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। राउत ने महाराष्ट्र की मंत्री मेघना बोर्डेकर के भाई की कथित मौत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेघना बोर्डेकर ने खुद डीजे के शोर से होने वाली परेशानियों के बारे में बात की थी। उन्होंने पिंपरी-चिंचवड़ की एक महिला का भी उल्लेख किया, जिसके बारे में राउत ने दावा किया कि तेज संगीत के कारण पैदा हुई बाधा की वजह से एंजुलेस समय पर नहीं पहुंच सकी।

अभिनव आकाश

संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में दुनिया का पारंपरिक नक्शा बदलने का प्रस्ताव पारित हो गया है। नक्शे को बदलने के लिए अफ्रीकी देश टोगो की ओर से क्रेकट द मैप मुहिम चलाई गई थी। इसे अफ्रीकन यूनियन यानी कि एयू का समर्थन मिला था। प्रस्ताव में खासतौर पर अफ्रीका का आकार और हिस्सों को ज्यादा सही ढंग से दिखाने की बात कही गई थी। यूएन में इस प्रस्ताव को भारत, फ्रांस और इंग्लैंड समेत 164 देशों का समर्थन मिला है। जबकि एकमात्र अमेरिका ने इसके खिलाफ वोट किया है। इसके अलावा छह देशों स्टीनिया, जॉर्जिया, लिदवानिया, मुल्दोवा, सर्बिया

और यूक्रेन ने वोटिंग से दूरी बनाकर रखी। यूएन में हुए इस मतदान से दुनिया भर के संस्थानों में इस्तेमाल होने वाले नक्शों में बदलाव आएगा। यह खबर कई सवालों को जन्म देती है। जैसे कि क्या अब दुनिया का नक्शा बदल जाएगा? मरकेटर मैप इक्वल अर्थ मैप में क्या अंतर है? आखिर 450 साल पुराने नक्शे ने दुनिया को इतना अलग क्यों दिखाया और नए नक्शे में अफ्रीका अचानक इतना बड़ा नज्द क्यों आया? संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन ने एक नए विश्व मानचित्र को मंजूरी दी है जिसमें महाद्वीपों का आकार एक दूसरे के मुकाबले ज्यादा सही दिखाया गया है। प्रस्ताव में कहा गया कि 16वीं सदी में नौवहन के उद्देश्य से तैयार %मर्केटर

प्रोजेक्शन% उपयोग अब तक धरती पर देशों और महाद्वीपों को दिखाने के लिए किया जाता था। इसमें देशों और महाद्वीपों का आकार उनके असली क्षेत्रफल से बड़ा या छोटा दिखता था। टोगो की पहल और अफ्रीकी देशों की अगुआई में लाए गए इस प्रस्ताव का मकसद खास तौर पर अफ्रीका के आकार को दुनिया के नक्शों में अधिक वास्तविक रूप में दिखाना है। इस फैसले से देशों और महाद्वीपों के क्षेत्रफल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस आकारों में बदलाव हो सकता है। क्योंकि, नया नक्शा सीमाएं नहीं, बल्कि नक्शे पर पृथ्वी को दिखाने का तरीका बदलने वाला है। भारत का नक्शा थोड़ा अलग दिख सकता है, लेकिन बड़ा



बदलाव नहीं होगा।

मान लीजिए आपके हाथ में एक सेब है। सेब एकदम गोल। ठीक हमारी पृथ्वी की तरह। अब अगर आप उस सेब का छिलका उतारकर मेज पर बिल्कुल सपाट रख दें यानी समतल रख दें और फैलाने की कोशिश करेंगे तो वह किनारे से फटेगा या फिर आपको उसे जबरदस्ती खींचना पड़ेगा। यह भी हो सकता है। कुछ ऐसा उदाहरण आप संतरे

को भी लेकर देख सकते हैं। जब आप संतरे को छीलते हैं और नीज पर रखते हैं तो शायद वो फैल भी सकता है या टूट भी सकता है। गोल धरती को चौकोर पन्ने पर उतारते वक्त भी बिल्कुल यही परेशानी आती है। करीब 450 साल पहले 1569 में गेराड्स मॉर्केटर ने यही नक्शा तैयार किया था। उस दौर में हवाई जहाज नहीं थे। लोग समंदर में जहाजों से महीनों सफर करते। नाविक पानी में भटक ना में गेराड्स मॉर्केटर ने नक्शे में रास्तों और दिशाओं को एकदम सीधी रेखाओं में रखा ताकि जहाजों को सही दिशा मिले। दिशाएं सीधी रखने के चक्कर में एक बड़ी भूल हुई। मार्केटर नक्शा समंदर में जहाजों को सही रास्ता दिखाते

के लिए तो शानदार था लेकिन उसने दुनिया के देशों का असली आकार खराब कर दिया था। यह प्रस्ताव गैर-बाध्यकारी है। मतलब, दुनियाभर में इस्तेमाल होने वाले सभी नक्शों को तत्काल मर्केटर से बदलना अनिवार्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य अधिक सटीक और समानुपातिक कार्टोग्राफिक मैपिंग को प्रोत्साहित करना है। वोट से पहले ह ने टोगो के विदेश मंत्री रॉबर्ट डूसी के हवाले से कहा, %मैप जाए इसलिए मार्केटर ने नक्शे में रास्तों का आकार देते हैं। वे शिक्षा को गाइड करते हैं, कल्पना को बढ़ावा देते हैं और सामूहिक सोच पर असर डालते हैं।धरती पर इंसानी सफर की बुनियाद अफ्रीका की सरजमीं से ही पड़ी, जिसे इतिहास

में ‘द ग्रेट माइग्रेशन’ का नाम मिला। वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि इसी महाद्वीप से निकलकर इंसान दुनिया के कोने-कोने में बसे और सभ्यताओं का बिस्मयकारी ताना बुना। अगर वक्त का अंजाम फेर दे देखिए—जिस भूभाग ने पूरी मानव जाति को पहचान दी, वही सदियों तक दुनिया के कागजों पर अपनी सही भौगोलिक पहचान और वास्तविक आकार के लिए संघर्ष करता रहा। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक अहम प्रस्ताव को हरी झंडी दी है, जो दुनिया के सामने देशों और महाद्वीपों का बिल्कुल सटीक और यथार्थवादी खाका पेश करेगा। दरअसल, गोल घूमती धरती को किसी सपाट कागज पर हूबहू उतार पाना कभी आसान नहीं रहा।

—> विकसित छत्तीसगढ़ की ओर मजबूत कदम —<

पर्यटन के जरिए नई पहचान गढ़ रहा छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पर्यटन विकास का स्वर्णिम अध्याय

प्राकृतिक संपदाओं, ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक आस्थाओं, जैव विविधता और समृद्ध जनजातीय संस्कृति से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ आज देश के सबसे उभरते हुए पर्यटन राज्यों में अपनी सशक्त पहचान बना रहा है। राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने, निवेश को प्रोत्साहन देने और स्थानीय समुदायों को पर्यटन से जोड़ने की पहल ने प्रदेश में पर्यटन विकास को नई गति प्रदान की है।



“

मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को सुलभ, समृद्ध और आकर्षक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय गौरव को देश-दुनिया तक पहुंचाया जाए। पर्यटन केवल भ्रमण का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक समृद्धि का मजबूत आधार है।

— श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



मधेश्वर पहाड़ बना विश्व रिकॉर्डधारी, छत्तीसगढ़ पर्यटन को मिली नई पहचान



छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले स्थित मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग की विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिकृति के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 'लार्जस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग' के रूप में मिली यह मान्यता प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करने वाला क्षण बताया। कुनकुरी ब्लॉक के मयाली गांव के समीप स्थित मधेश्वर पहाड़ प्राकृतिक आस्था का अनूठा केंद्र है। राज्य सरकार के प्रयासों से जशपुर तेजी से पर्यटन और एडवेंचर गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।



राजधानी रायपुर बना सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन का प्रवेश द्वार



राम मंदिर, मां कौशल्या धाम, ट्राइवल म्युजियम, पुरखौती मुक्तांगन, ऊर्जा पार्क, नंदनवन एवं अन्य प्रमुख स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़कर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती दी गई है। धार्मिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।



जशपुर की वादियों से उठी चाय की सुगंध, कृषि और पर्यटन को मिली नई उड़ान



छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से जशपुर जिले का सारूडीह चाय बागान आज राज्य की नई पहचान बनकर उभरा है। लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में फैला यह बागान पर्वतों और घने जंगलों के बीच स्थित है, जो पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण दोनों को बढ़ावा दे रहा है। राज्य की पहली चाय प्रसंस्करण इकाई बालाछापर में स्थापित की गई है, जहां काली और हरी चाय का उत्पादन शुरू हो चुका है। वर्मी कम्पोस्ट आधारित जैविक खेती से तैयार जशपुर की चाय गुणवत्ता और स्वाद के लिए विशेष पहचान बना रही है। चाय बागान ने अनुपयोगी भूमि को हरियाली में बदलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए हैं। आज सारूडीह चाय बागान छत्तीसगढ़ की कृषि नवाचार, ग्रामीण विकास और पर्यटन क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है।



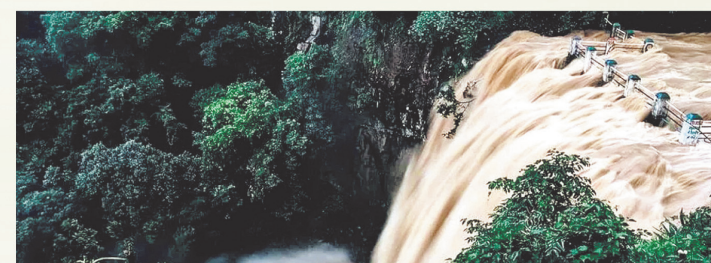
सिरपुर और बारनवापारा : विरासत और वन्य पर्यटन का अद्भुत संगम



सिरपुर की ऐतिहासिक धरोहर, प्राचीन मंदिर और पुरातात्विक महत्व शोधार्थियों एवं पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। बारनवापारा की जंगल सफारी और वन्य जीवन प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पर्यटन सुविधाओं के विकास से स्थानीय ग्रामीण समुदायों की आय में वृद्धि हो रही है।



मैनपाट : छत्तीसगढ़ का शिमला, प्रकृति और संस्कृति का संगम



मैनपाट अपनी ठंडी जलवायु, हरियाली और तिब्बती संस्कृति के कारण 'छत्तीसगढ़ का शिमला' एवं 'मिनी तिब्बत' कहलाता है। टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, जलजली और उल्टा पानी जैसे आकर्षण इसे विशेष बनाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, रिसॉर्ट विकास और मैनपाट कॉर्नर के माध्यम से इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है।



पर्यटन में निवेश का बढ़ता विश्वास



होटल, रिसॉर्ट, वेलनेस सेंटर, इको-रिसॉर्ट और पर्यटन अधोसंरचना में करोड़ों रुपये के निवेश की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। इनसे आधुनिक सुविधाओं का विकास होगा तथा हजारों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है।



पर्यटन क्षेत्र के लिए तैयार हो रही प्रशिक्षित युवा शक्ति



पर्यटन विभाग के सहयोग से सैकड़ों युवाओं को गाइड प्रशिक्षण, संचार कौशल, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण, पर्यटक प्रबंधन और आतिथ्य सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षित युवा प्रदेश की विरासत को देश-विदेश के पर्यटकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।



सोनाखान-कसडोल : इको-टूरिज्म विकास का नया मॉडल



नारायणपुर स्थित हांडावाड़ा जलप्रपात

जशपुर स्थित राजपुरी जलप्रपात

शहीद वीर नारायण सिंह की पावन कर्मभूमि सोनाखान और प्राकृतिक संपदा से समृद्ध कसडोल क्षेत्र को इको-टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। घने वन, झरने, जैव विविधता, वन्यजीव और आदिवासी संस्कृति से समृद्ध यह क्षेत्र अब पर्यटन मानचित्र पर से तेजी से उभर रहा है। इको-टूरिज्म से स्थानीय युवाओं को गाइड सेवा, परिवहन, होमस्टे, हस्तशिल्प, खाद्य सेवाओं एवं पर्यटन आधारित उद्यमों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का आदर्श मॉडल भी है।

पर्यटन से बढ़ रहा रोजगार •



मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था •



सशक्त हो रहा ग्रामीण छत्तीसगढ़



प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक गौरव और आधुनिक विकास का अनूठा संगम आज छत्तीसगढ़ को देश के सबसे संभावनाशील पर्यटन राज्यों में स्थापित कर रहा है। पर्यटन के माध्यम से छत्तीसगढ़ नई पहचान, नई ऊर्जा और नए अवसरों के साथ विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।



एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत

रायपुर। एनएसयूआई छत्तीसगढ़ अध्यक्ष नीरज पांडेय पर 29 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। पीड़ित राजू सोनकर ने अपनी शिकायत में नीरज पांडेय के साथ उनके भाई दीपक पांडेय और चाचा इंद्रासन पांडेय के नाम भी शामिल किए हैं। उसका दावा है कि उसे अपनी पत्नी के लिए मंत्रालय में नौकरी दिलाने और रत खदान का काम दिलाने का भी भरोसा दिया गया था। इसके अलावा सिप्ला कंपनी की एजेंसी या डीलरशिप दिलाने की बात कहकर भी रकम लिए जाने का आरोप है। पीड़ित ने अलग-अलग भुगतान और बैंक ट्रान्जेक्शन का भी ज़रूफ किया है। उसका कहना है कि रकम देने के बाद काम नहीं होने पर उसने पैसे वापस मांगे, लेकिन उसे रकम नहीं मिली। पीड़ित राजू सोनकर ने अपने आवेदन में कहा है कि उसे अपनी सुरक्षा को लेकर डर है। पीड़ित ने कहा कि अगर उसके साथ कोई अग्रिय घटना होती है, तो इसके लिए नीरज पांडेय, उनके भाई दीपक पांडेय और चाचा इंद्रासन पांडेय जिम्मेदार होंगे।

प्रदेश में पटवारियों के 200 पदों पर सीधी भर्ती की मंजूरी, 26 जिलों में होगी नियुक्ति

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में पटवारी के 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। शासन की ओर से 6 सितंबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, जिलों में स्वीकृत रिक्त पदों पर भर्ती सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी। पटवारी भर्ती छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया CG Vyapam के पोर्टल पर भर्ती प्रस्ताव की प्रविष्टि के बाद शुरू होगी। शासन के आदेश के अनुसार सबसे अधिक 15-15 पद सारंगढ़-बिलाईगढ़, गरियाबंद, बालाढ़, बेमेतरा और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों में हैं। वहीं अन्य जिलों में पदों का वितरण इस प्रकार है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रिक्त पदों पर भर्ती के दौरान प्रचलित आरक्षण और भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया चयन मंडल के माध्यम से पूरी होगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित जिला कलेक्टरों की भी आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति भेजी है। वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को भी भर्ती संबंधी सूचना दी गई है। पटवारी के 200 पदों पर भर्ती की मंजूरी से राजस्व विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा अवसर मिलेगा। हालांकि, आवेदन की तारीख, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा शुल्क और अन्य पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी आधिकारिक भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक 9 सितम्बर को

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 09 सितम्बर 2026 को पूर्वाह्न 11: 30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद कक्ष एम-5/20 में होगी।

सात सिंचाई योजनाओं के लिए 30.74 करोड़ रुपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सात प्रमुख सिंचाई योजनाओं के लिए कुल 30 करोड़ 74 लाख 39 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि का उपयोग नहरों के जीर्णोद्धार, रिमॉडलिंग, सीसी लाइनिंग और भूमिगत पाइपलाइन निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाएगा। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायपुर जिलेवार स्वीकृत कार्यों में बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के बलौदा शाखा नहर (विवरक 11 एवं 12) में रिमॉडलिंग, सीसी लाइनिंग एवं पक्के निर्माण कार्यों के लिए 4.99 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, इससे 339.05 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी। इसी प्रकार सोडूर परियोजना (बेन्द्री विवरक नहर) के भाटापारा शाखा नहर के बेन्द्री विवरक नहर की रिमॉडलिंग व सीसी लाइनिंग के लिए 4.82 करोड़ मंजूर। इससे 355 हेक्टेयर क्षेत्र को पानी मिलेगा।

राज्य सरकार ने कॉलेज छात्रों को दी बड़ी राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्नातक प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में एटीकेटी के कारण तीसरे वर्ष में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने ऐसे विद्यार्थियों को अकादमिक सत्र 2026-27 के पांचवें सेमेस्टर में सशर्त प्रावधिक प्रवेश देने की अनुमति दे दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, स्नाक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में एटीकेटी प्राप्त विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें अकादमिक सत्र 2026-27 के पांचवें सेमेस्टर में सशर्त प्रावधिक प्रवेश दिया जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की एटीकेटी परीक्षाएं नियमित विद्यार्थियों के साथ निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार उत्तीर्ण कराना अनिवार्य होगा। एटीकेटी के कारण तीसरे वर्ष में प्रवेश पर लगी रोक को लेकर हल्दू और पीआरएसयू अध्यक्ष पुनेश्वर लहरे के नेतृत्व में छात्रों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था।

राजधानी/छत्तीसगढ़

भाजपा के नेतृत्व में सशक्त हो रहा पिछड़ा वर्ग : तोखन साहू

■ भाजपा ओबीसी मोर्चा की संभागीय बैठक

रायपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा की संभागीय बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू शामिल हुए। उन्होंने ओबीसी समाज की एकजुटता, सामाजिक सशक्तीकरण और संगठन की मजबूती पर विस्तार से अपने विचार रखे।

तोखन साहू ने ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू एवं उनकी पूरी टीम को प्रदेश के कोने-कोने में जाकर ओबीसी समाज को जोड़ने, जागरूक करने और संगठन को मजबूत बनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग की लगभग 67 जातियां आती हैं। हमारी जातियां भले अलग-अलग हों, लेकिन हमारी परंपराएं, रहन-सहन और सांस्कृतिक मूल्य एक है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें किसी छोटे दायरे में नहीं बंधना है, बल्कि अपनी एकजुटता को समाज की सबसे बड़ी शक्ति बनाना है।

जमीन सीमांकन के लिए नहीं काटने पड़ेंगे तहसील के चक्कर, ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया

रायपुर। राज्य सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए जमीन के सीमांकन की प्रक्रिया को बेहद आसान, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है। अब जमीन मालिकों को नाप-जोख या सीमांकन के लिए तहसील कार्यालयों और सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

नए डिजिटल सिस्टम में सीमांकन आवेदन के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि सिर्फ लोक सेवा केंद्र (एस्प/चॉइस सेंटर) और राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिटिज़न पोर्टल या सेवासेतु के माध्यम से ही आवेदन जमा किए जा सकेंगे, जिससे सीमांकन को ऑफलाइन या मैनुअल आवेदन को तहसील स्तर से दर्ज करने की व्यवस्था को खत्म की जा रही है। आवेदन सीधे संबंधित तहसीलदार की आईडी में ट्रान्सफर हो जाएंगे। राजस्व निरीक्षक द्वारा भी अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जिससे आवेदक को आवेदन के संबंध मे सभी स्तर के जानकारी उपलब्ध होती रहेगी।

कृष्ण राम महापात्र बने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 16वें चीफ जस्टिस

■ राज्यपाल डेका ने दिलाई शपथ

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने न्यायाधिपति श्री कृ्ण राम महापात्र को सोमवार को लोकभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम् में उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। इसके पूर्व श्री कृष्ण राम महापात्र उड़ीसा हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज के पद पर कार्यरत थे। राज्यपाल श्री डेका ने मुख्य न्यायाधीश श्री कृष्ण राम महापात्र को राष्ट्रपति द्वारा जारी मूल वारंट की प्रति सौंपी। राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश श्री महापात्र को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश

डिजिटल क्रॉप सर्वे में सारंगढ़-बिलाईगढ़ प्रदेश में अत्वल

रायपुर। डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) के प्रभावी और बेहतर क्रियान्वयन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले ने प्रदेश स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश स्तरीय रिपोर्ट में जिले ने 87 प्रतिशत कार्य के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे में सर्वाधिक कार्य करने वाले प्रदेश के शीर्ष तीन जिलों में सारंगढ़-बिलाईगढ़ पहले स्थान पर हैं, जबकि खैरागढ़ 86 प्रतिशत के साथ दूसरे और कोरिया 81 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। 6 सितंबर 2026 को शाम 4.30 बजे तक की तहसीलवार प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 53 हजार 524 प्लॉटों के विरुद्ध 47 हजार 350 प्लॉटों का सर्वे पूर्ण किया जा चुका है, जो 88.45 प्रतिशत है। जिले में 35 हजार 476 सर्वे अनुमोदित किए जा चुके हैं।

केंद्रीय राज्यमंत्री साहू ने कहा कि यह पूरे देश के लिए गर्व का विषय है कि भारत की आधी से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य ओबीसी समुदाय और तेली समाज से निकले बेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। यह पूरे ओबीसी समाज के लिए अत्यंत गौरव का विषय है।

उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में ओबीसी समाज से दो प्रधानमंत्री बने हैं – एचडी देवगौड़ा जी (1996-1997) वोक्वालिंगा समुदाय से और नरेंद्र मोदी (2014 से निरंतर) घांची/तेली समुदाय से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मेहनत और संघर्ष से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचकर यह साबित किया है कि नए भारत में अवसर किसी परिवार की जागीर नहीं, बल्कि मेहनत और प्रतिभा के आधार पर हासिल किए जा सकते हैं।

तोखन साहू ने कहा कि 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ और 1955 में उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार में मंडल आयोग का गठन हुआ। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।



और पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू किया, जिसके बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा साहनी मामले में इसे संवैधानिक मान्यता दी।

उन्होंने कहा कि इसके बावजूद लंबे समय तक पिछड़ा वर्ग आयोग को वह अधिकार नहीं मिले, जो उसे मिलने चाहिए थे। आजादी के बाद लगभग 75 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में करीब छह दशक तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन पिछड़े वर्गों के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के

पत्रकारिता में सत्य, तथ्य और जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता हो : डेका

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने एआई एवं मीडिया शोध केंद्र का उद्घाटन भी किया।

इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने विश्वविद्यालय के प्रेरणा स्त्रोत स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की प्रतिमा में श्रद्धा-सुमन अर्पित किये। उन्होंने स्व. ठाकरे जी के सानिध्य में बिताए गए अवसरों और प्रेरणादायी उद्धरणों को साझा किया।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन विश्वविद्यालय के लिए विशेष महत्व रखता है। सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के प्रसार और नारी सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके नाम पर कन्या छात्रावास का नामकरण छात्राओं को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह छात्रावास दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उनकी उच्च शिक्षा और प्रतिभा विकास में सहायक होगा।

राज्यपाल ने कहा कि आर्टिफिशियल

लिए अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए।

तोखन साहू ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सामाजिक न्याय को केवल बातों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उसे धरातल पर उतारा गया। 2018 में 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उसे सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्रदान की गईं। 2019 में अलग से मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय बनाया गया, जिससे मछुआरा समाज और पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को लाभ मिला।

उन्होंने बताया कि 2017 में क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये सालाना की गई, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को आरक्षण का लाभ मिल सके। ओबीसी समुदाय की छोटी-बड़ी सभी जातियों तक आरक्षण का लाभ समान रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से न्यायमूर्ति रोहिणी आर्योग का गठन किया गया। 2021



इंटेलिजेंस के आगमन से मीडिया और पत्रकारिता के स्वरूप में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समय में विश्वविद्यालय में स्थापित मेधा एआई एवं मीडिया शोध केंद्र विद्यार्थियों को नई तकनीकों को समझने तथा उनके जिम्मेदार और प्रभावी उपयोग के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है और इसकी विश्वसनीयता बनाए रखना प्रत्येक पत्रकार का दायित्व है। समाचारों में तथ्य, सत्य और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के संबंध में समाचार प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की पूर्ण पुष्टि आवश्यक है, क्योंकि ऐसा समाचार का प्रभाव व्यक्ति और समाज दोनों पर पड़ सकता है।

श्री डेका ने कहा कि सोशल मीडिया के वर्तमान दौर में सूचनाओं का तेजी से प्रसार हो

■ उपकरण बंद होने पर भी दौड़ रहे मीटर

रायपुर। छत्तीसगढ़

विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रमाणित फर्जीवाड़ा का दस्तावेज सौंपा है। डॉ. महंत ने प्रदेश भर में लगाए जा रहे तथाकथित स्मार्ट मीटरों में सामने आ रहे भारी फर्जीवाड़े और उपभोक्ताओं पर थोपे जा रहे बेतहाशा बिजली बिलों को लेकर राज्य सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ कड़ा प्रतिकार दर्ज कराया है। डॉ. महंत ने इसे स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता की जेब पर खुला डाका करार दिया है।

साक्ष्यों के साथ उजागर हुआ खेल्.. डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा प्रदेश के जिलों और नगरीय निकायों में

आनन-फानन में स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं। जब से ये मीटर लगे हैं, तब से आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल 2 से 4 गुना तक बढ़ चुके हैं। हजारों उपभोक्ताओं ने लिखित और प्रमाणित साक्ष्यों के साथ शिकायतें दर्ज कराई हैं। कई मामलों में तो उपभोक्ताओं ने घर के सारे उपकरण बंद रखकर भी मीटर की तेज रफ्तार रीडिंग को वीडियो व अन्य माध्दम से प्रमाणित किया है। बंद घरों में भी यूनितों का अंधाधुंध बढ़ना यह साबित करता है कि यह केवल सामान्य तकनीकी ग़ुटि नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में किया गया गंभीर फर्जीवाड़ा है।

नेता प्रतिपक्ष ने तीखा प्रहार करते हुए कहा, महंगाई की मार झेल रही जनता पर दोहरा प्रहार है,प्रदेश का गरीब, किसान और

में नीट के ऑल इंडिया कोटा की एमबीबीएस और पीजी सीटों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। इससे हर वर्ष लगभग 4,000 ओबीसी युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 105वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सरकारों को अपनी ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार वापस दिया गया। यही वास्तविक सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। भाजपा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ओबीसी समाज को सम्मान, अधिकार और अवसर देने का कार्य किया है। उन्होंने ओबीसी समाज के सभी लोगों से एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय जामलाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, प्रदेश ओबीसी मोर्चा प्रभारी लखन साहू, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा अशोक साहू सहित संगठन के पदाधिकारी, ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

स्मार्ट मीटर के नाम पर फर्जीवाड़ा प्रमाणित : महंत



मध्यम वर्ग पहले से ही कमरतोड़ महंगाई और बढ़ी हुई बिजली दरों से त्रस्त है। ऐसे में %पारदर्शिता% का ढोंग रचकर स्मार्ट मीटरों के जरिए जनता पर फर्जी बिलों का असहनीय बोझ लाद दिया गया है। जब पीड़ित उपभोक्ता शिकायत लेकर जाते हैं, तो बिजली विभाग के स्थानीय अधिकारी गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर उन्हें टरका रहे हैं, बिना का का यह संवेदनहीन रुख असहनीय है। डॉ. महंत ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने तत्काल प्रभाव से टेस्टिंग शुल्क समाप्त नहीं किया और स्मार्ट मीटरों की लूट पर लगाम नहीं लगाई, तो कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मिलकर बिजली कार्यालयों का घेराव करेगी और सड़क से लेकर विधानसभा तक उग्र आंदोलन छेड़ेगी।

// कार्यालय सेनानी, पुलिस प्रशिक्षण शाला, जगदलपुर, जिला-बस्तर छ.ग. //

E-mail: aptsjdr@gmail.com

क्रमांक:-पीटीएस/सा.अ./निविदा/R/ 681 / 2026, जगदलपुर, दिनांक 31/08/2026			
// निविदा आमंत्रण सूचना //			
सेनानी, पुलिस प्रशिक्षण शाला, जगदलपुर में नीचे उल्लिखित निर्माण कार्य के लिए ई पंजीकृत "डी" श्रेणी एवं उच्च श्रेणी ठेकेदार से प्रभावी अनुसूची दर ०1.01.2015 के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए पृथक-पृथक मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। कार्यालय से निविदा फार्म विक्री की अंतिम तिथि 28.09.2026 समय अपराह्न 5.30 बजे तक। पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय में निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 30.09.2026 समय अपराह्न 5.00 बजे तक। निविदा खोलने की तिथि ०1.10.2026 समय अपराह्न 12.30 बजे तक। निविदा खोलने का स्थान-कार्यालय सेनानी, पुलिस प्रशिक्षण शाला, लालबाग जगदलपुर, जिला-बस्तर (छगण) है।			
क्र.	कार्य का नाम व कार्य स्थल	प्रशासकीय स्वीकृत राशि	धरोहर राशि
01	प्रधान आरक्षक बैक प्रथम तल निर्माण कार्य	18,39,000.00	18390.00

नोट:-

01. निविदा प्रपत्र कय हेतु आवेदन पत्र के साथ चालान ("लेखा शीर्ष 0055-पुलिस मिसलेनियस, 800-अन्य प्रसिधे") शीर्ष में राशि रु. 750/- जमा किया) की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर निविदा प्रपत्र प्रदान की जावेगी।

02. निविदा संबंधित अन्य जानकारी एवं शर्तें कार्यालय सेनानी पुलिस प्रशिक्षण शाला लालबाग जगदलपुर के कार्यालयीन दिवस / समय में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते है।

सेनानी	
पुलिस प्रशिक्षण शाला	
जी-262703127/5	जगदलपुर (छ.ग.)

मेट्रो का सफर और जैन-जी से मोदी का संवाद

सनत जैन

जंतर मंतर पर कॉंकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्रों से सीधा संवाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा मेट्रो सफर से श्रीराम कॉलेज तक की हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो में छात्रों से मुलाकात की और उसके बाद छात्रों के बीच जाकर उनसे संवाद किया। छात्रों से मुलाकात के बीच पीएम मोदी का अंदाज वही था जो राहुल गांधी का था। राजनीति के पंडितों का कहना है, अब राहुल गांधी बिसात बिछा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को उस पर चलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के इस संवाद की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्ली और राजनीतिक हलकों में देखने को मिल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी मे छात्र संघ के कुछ ही दिनों में चुनाव होना है। इसे एक चुनावी रैली के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संवाद कार्यक्रम में जिस तरह से 2013 की घटनाओं का उल्लेख किया। छात्रों को बताया कि 2013 में क्या स्थिति थी आज उससे बहुत बेहतर स्थिति है, और 2047 तक भारत में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत रिसर्च और इनोवेशन का दुनिया का सबसे बड़ा हब होगा। भारत में ओलंपिक का आयोजन होगा। उन्होंने छात्रों के साथ एक भविष्य का विजन रखा। श्रीराम कॉलेज की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने छात्रों से कहा, की पूर्व के छात्र ओजी हैं, जिन्होंने सारी दुनिया में धूम मचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उपलब्धियां बताई और 2013 की केंद्र सरकार पर हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में स्मार्टफोन के उत्पादन और डिफेंस उत्पादन को लेकर छात्रों के सामने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा, देश में अलग प्रजाति के लोग हैं, हर चीज में वह नाराज फूफा बनते हैं। ऐसे सभी नाराज फूफा होम्योपैथी की एक मीठी गोली देते ही सामने आ गए हैं। उनका इशारा 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए उस कथन की ओर था जिसमें उन्होंने दिमागी नक्सली को लेकर अपनी बात कही थी। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 100 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी शाम को ट्रैफिक के समय गाड़ी से यदि कॉलेज जाते तो लंबा जाम लगता, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी यात्रा मेट्रो से की। मेट्रो में बच्चों और उनके माता-पिता से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संवाद चर्चा का विषय बन रहा है। इसके दो कारण हैं, एक तो वह राहुल गांधी जो करते हैं वही वह करने लगे हैं, इससे एक धारणा यह बन रही है कि अब राहुल गांधी की बिसात पर चलना उनकी मजबूरी हो गई है। दूसरी जिस तरह से छात्रों के बीच राहुल गांधी जाकर उनकी बात सुनते हैं, छात्र गुंज का मन से युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। अब वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को करना पड़ रहा है। इससे एक संदेश यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हुए हैं। केंद्र सरकार, भाजपा तथा मीडिया को अब पीछे चलना पड़ रहा है, जिसके कारण दिन-प्रतिदिन राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है। यह राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है। बहरहाल जंतर मंतर पर कॉंकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद से सारे देश में प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई है। छोटे-छोटे बच्चे, किसान एवं अन्य वर्ग के लोग भी अपनी बात मुखरता के साथ कहने सड़कों पर उतर रहे हैं। अपनी बात मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे देश का माहौल बदल गया है। अब आंदोलनकारी आक्रामकता के साथ अपनी बात मनवा रहे हैं।

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे....)

ग्रन्थ का कलेवर अत्यधिक बढ़ गया है। पुराण-साहित्य रूप अगाध रत्नाकर को छोटे से शराव (कूजे) में बन्द कर देना सर्वथा असम्भव है। ग्रन्थ के नाम-करण के अनुसार भी पुराणों का दिग्दर्शन मात्र करा देना ही अन्वर्थता का परिचायक है। गर्ज है कि इस ग्रन्थ में अभी तक जो कुछ भी लिखा जा चुका है वह उतनाही हमारी पूर्वकृत प्रतिज्ञाके पालनका पर्याप्त साधक हो सकता है। इसलिये हम मङ्गलमय भगवा-?को कोटिशः प्रस्ताम करते हुये इस ग्रन्थ का उपसंहार कर देना उचित समझते हैं।

यदिहास्तित तदन्यत्र यत्रेहास्तित न तत्क्वचित् के अनुसार इस लोक और परलोक का वह कोई विषय नहीं जोकि पुराणों में अङ्कित न हो? यदि मैं यह भी कह दूँ तो अतिशयोक्ति न होगी, कि वेदों को छोड़कर समस्त वाङ्मय उपजीव्य-उपजीवी सम्बन्ध से पुराणभूलकता पर ही अवलम्बित है। हमारा दावा

है कि आप किसी भी भाषा के बेजोड़ एवं मौलिक कहे जाने वाले ग्रन्थ को उड़ाइये, हम तत्प्रतिपादित विषय का सर्वाङ्ग-पूर्ण वर्णन पुराण ग्रन्थों में लिखा दिखा दंगे।

कविकुलतिलक कालिदास आदि भारतीय अमर कवियों ने तो स्वनि-मित ग्रन्थों को कपोलकल्पिता के परिहारार्थ स्पष्ट ही अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन्पूर्वसूरिभिः कहते हुवे व्यास वाल्मीकि प्रभृति महर्षियों के निर्माण किये हुवे पुराणैतिहास ग्रन्थों को अपने अपने काव्यों का आधार स्वीकार किया ही है परन्तु पाश्चात्य पण्डितों के वनाये हुये बड़े से बड़े ग्रंथों के कथानक भी नाममात्र के भेद से पौराणिक आख्यानों के साथ अपरिमाजीन्य समता रखते हैं- यह बात हमने हिन्दी में अनूदित हुवे टालस्टाय, होमर, मिल्टलन दांते शेक्सपियर श्रादि पाश्चात्य पण्डितों के ग्रन्थों के परिशीलन से अनुसन्धानपूर्वक निश्चित की है।

क्रमशः....

एथनॉल मिश्रित पेट्रोल पर बढ़ रही है भाजपा समर्थकों की नाराजगी

शेखर गुप्ता

यह बहस गर्म है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 7.8 फीसदी की दर से बढ़ा या 2.6 फीसदी की दर से। टीवी स्टूडियो में बैठे लोग जिस तरह रातोरात अर्थशास्त्री बनकर एक-दूसरे की आलोचना कर रहे थे, उसे देखकर सर्जियो गोर को भी जरूर काफी मजा आया होगा। यह सब मजेदार है लेकिन राजनीति के नजरिये से यह एक गलत बहस है। वैसे भी अब दूसरी तिमाही दो तिहाई से ज्यादा गुजर चुकी है तो यह बहस ज्यादा दिन नहीं चलेगी।

सवाल यह है कि यह बहस गलत क्यों है और सही बहस क्या है? यह केवल इसलिए गलत नहीं है कि यह अस्थायी है। बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इस ध्ववीकृत माहौल में लोग बहुत शिदत के साथ अपने एथनॉलितिक सिद्धांतों में यकीन करते हैं। कोई भी मतदाता जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर अपना मन नहीं बदलेगा। जो बहस मायने रखती है वह एकदम अलग है-एथनॉल मिश्रण को लेकर गुस्सा।

वाहन मालिकों का एक बड़ा वर्ग, खासकर हिंदू मध्य वर्ग मोदी-शाह की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्पित मतदाता है। वे बेहद नाराज हैं। हमने इस पर कोई सर्वे नहीं देखा है लेकिन बोते कुछ अह्मियों में मैं ऐसे ढेर सारे लोगों से मिला जिनमें हवाई अड्डों पर मिले अजनबी, शादी समारोहों में मिले लोग, होटल की लॉबी में मिले लोग, आंगुत्क, उबर चालक, आदि शामिल थे। ये सभी बेहद गुस्से में नजर आए। सबके पास एक ही वजह थी-हमें पेट्रोल मिला एथनॉल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कैसे किया जा सकता है?

मोदी सरकार के विकास के आंकड़ों का बचाव करने वाले भी उसी तादाद में मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब यह है कि जिस आधार को भाजपा इतनी गंभीरता से लेती है वह सिर्फ इसी एक मुद्दे को लेकर उससे नाराज है।

बेशक सभी लोग मानते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में जीत हासिल की और दुनिया, जिसमें पुतिन



और शी भी शामिल हैं, उनके नेता का सम्मान करती है-‘जैसा कि हमने अभी विश्वकेक में देखा।’ तो फिर मुझे यह ‘मिलावटी’ पेट्रोल देकर सजा क्यों दी जा रही है?

मोटे तौर पर उनकी चिंताएं और सवाल ये हैं- मुझे इससे क्या फायदा मिलता है? मैं उतनी ही कीमत चुकाता हूं लेकिन मुझे कम माइलेज मिलता है जैसा कि सरकार खुद स्वीकार करती है। इसके अलावा मैं अभी भी अपनी गाड़ी की ईएमआई चुका रहा हूं जबकि इससे इंजन को नुकसान भी हो सकता है। मेरे देश को इससे क्या फायदा है? अगर कोई फायदा है तो मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा?

मुझे विकल्प क्यों नहीं दिया गया? पहले तो कोई मुझे यह नहीं बताता कि मुझे ईबीपी (एथनॉल मिश्रित पेट्रोल) का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। फिर कहा जाता है कि इसे इस्तेमाल करो या फिर पैदल चलो। मेरे कह या मेरे त्याग का फायदा किसे मिल रहा है?

ये अहम सवाल हैं और संभवतः सरकार के पास इनके जवाब भी हैं। हैरानी की बात है कि उसने अपने मतदाताओं को विश्वास में लेने की कोई कोशिश नहीं की।

अगर परीक्षा घोटालों की लगातार सामने आती घटनाओं के अलावा कोई एक मुद्दा है जिस पर भाजपा का आधार वर्ग नाराज है तो वह एथनॉल

ज्ञान/मीमांसा

उत्तर प्रदेश 2027: चुनावी बिसात और बदलते समीकरण

अशोक भाटिया

उत्तर प्रदेश की राजनीति को भारतीय लोकतंत्र का हृदयस्थल माना जाता है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ के गलियारों से होकर गुजरता है, यही कारण है कि देश के इस सबसे बड़े सूबे में होने वाली हर छोटी-बड़ी राजनीतिक हलचल का असर राष्ट्रीय फलक पर साफ दिखाई देता है। वर्ष 2026 की समाप्ति के करीब आते ही और 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट के साथ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के बीच शह-मात का खेल पूरी तरह से शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने सूबे की राजनीतिक जमीन को जो नई शकल दी थी, उसके बाद हर दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होकर इतिहास रचने की कवायद में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के सहारे दस साल के सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। इस बार का चुनाव केवल पारंपरिक नारों या वादों पर आधारित नहीं रहने वाला, बल्कि यह जमीन पर रची जा रही नई सामाजिक और गठबंधन राजनीति की प्रयोगशाला बनने जा रहा है।

इस राजनीतिक उठापटक और नए समीकरणों के निर्माण के बीच हाल ही में लखनऊ से एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक खबर सामने आई, जिसने राज्य के सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा कॉंकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के बीच लखनऊ में लगभग 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे तक चली बंद कमरे की मेरठान मुलाकात ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। इस मुलाकात के मायने केवल एक शिष्टाचार भेंट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह 2027 के महासमर से पहले उत्तर प्रदेश की युवा और छात्र राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। आशुतोष रांका और अखिलेश यादव के बीच हुई इस चर्चा के केंद्र में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के नीजवानों के मुद्दे, लगातार होती परीक्षाओं के पेपर लीक, बेरोजगारी, छात्रों की समस्याएं और उत्तम शिक्षा में आ रही गिरावट जैसे विषय शामिल रहे।

पार्टी के भीतर और बाहर इस मुलाकात को प्लान 2027 के एक अहम हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में



एक नया और बेहद जागरूक मतदाता वर्ग तैयार हो चुका है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक जैन-जी या पहली बार मतदान करने वाले युवा कहते हैं। यह युवा वर्ग पारंपरिक जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर रोजगार, निष्पक्ष परीक्षाओं और आधुनिक अवसरों की मांग कर रहा है। अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं कि केवल पारंपरिक मुस्लिम-यादव समीकरण या केवल सामान्य गठबंधनों के बूते भाजपा जैसी विशाल और साधन-संपन्न चुनावी मशीनरी को मात देना असंभव है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद सपा अब छोटे-छोटे वैचारिक समूहों, छात्र संगठनों और युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरों को अपने पाले में लाकर भाजपा के उस युवा वोट बैंक में संघ लगाना चाहती है, जो कभी भगवा दल की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। रांका और अखिलेश यादव की यह मुलाकात इस बात की तस्दीक करती है कि विपक्ष इस बार युवाओं के आक्रोश को एक ठोस राजनीतिक वोट बैंक में बदलने की मुकम्मल तैयारी कर चुका है।

हालांकि, इस मुलाकात पर भाजपा ने भी फौन तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा प्रवक्ताओं का कहना है कि विपक्ष के पास कोई ठोस नीति या विकास का एजेंडा नहीं है, इसलिए वह केवल भ्रम फैलाने और छोटे-छोटे संगठनों के सहारे अपनी डूबती नैया बचाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन राजनीति के जानकार इसे अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना ​​है कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके मूल में युवाओं और छात्रों का आंदोलन या उनका असंतोष ही रहा है। ऐसे में सीजेपी जैसी युवा केंद्रित ताकतों और सपा का करीब आना भविष्य के एक नए और बड़े सामाजिक-राजनैतिक मोर्चे की बुनियाद रख सकता है।

यदि हम उत्तर प्रदेश की समूची राजनैतिक बिसात पर नजर डालें, तो इस समय सबसे बड़ा टकराव नरेंद्रिव यानी विमर्श गढ़ने को लेकर चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस बार आरक्षण और संविधान को अपनी राजनीति के केंद्र में रख

दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को संविधान बचाओ के नारे से जो अप्रत्याशित लाभ मिला था, अखिलेश यादव उसे 2027 तक कायम रखना चाहते हैं। हालिया महीनों में उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की स्थिति, 69000 शिक्षक भर्ती का विवाद और पिछड़े-दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व को लेकर सपा ने एक आक्रामक रुख अख्तियार किया है। अखिलेश यादव लगातार जनसभाओं और सोशल मीडिया के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान सत्ताधारी दल दलितों और पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। इस नरेंद्रिव के जरिए सपा सीधे तौर पर भाजपा के गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलित वोट बैंक पर निशाना साध रही है, जिसने पिछले एक दशक से भाजपा की जीत में रोड़ की हड्डि का काम किया है।

सपा की इस रणनीति के जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी खामोश नहीं बैठी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने अपनी संगठन मशीनरी को पूरी तरह से चुनावी मोड़ में डाल दिया है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर का ढांचा माना जाता है। पार्टी ने इस बार कागजी दावों को खारिज करते हुए हर एक बूथ कमेट्री का भौतिक सत्यापन शुरू किया है। खासकर उन बूथों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जहां पिछले चुनाव में विपक्ष को बहुत मिली थी। इसके साथ ही, भाजपा सरकार अपनी कानून-व्यवस्था की सखा छवि, बुनियादी ढांचे का विकास (जैसे एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारे) और केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के एक बड़े नेटवर्क के भरोसे मैदान में उतर रही है। भाजपा का मानना ​​है कि विकास और सुशासन का उनका यह डबल इंजन मॉडल विपक्ष के जातिगत ध्ववीकरण के प्रयासों को विफल कर देगा।

लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन के भीतर की आंतरिक खींचतान भी पूरी तरह सहत पर आ चुकी है। गठबंधन में शामिल छोटे दल जैसे निषाद पार्टी के डॉ. संजय निषाद, अपना दल (सोनेलाल) की अनुग्रिया पटेल और सुभाषणा के ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और सीटों के सम्मानजनक बंटवारे के लिए भाजपा पर लगातार दबाव बना रहे हैं। हाल ही में एक सार्वजनिक मंच पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के भावुक होने और

आंसुओं के छलकने की घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भारी उबाल ला दिया था। जहां संजय निषाद ने इसे अपने समाज को हक न मिल पाने की पीड़ा बताया, वहीं अखिलेश यादव ने तुरंत इस पर तंज कसते हुए इसे भाजपा के साथ जाने का पश्चाताप और प्रार्थाश्चित करार दे दिया। यह घटना दर्शाती है कि निषाद और अन्य अति-पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को लेकर दोनों पक्षों में कितनी जबर्दस्त रस्साकशी चल रही है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि निषाद समाज भी उनके पीडीए का एक अभिन्न हिस्सा है और यदि उनकी सरकार आती है, तो वे जातीय जगनगणा करारकर हर समाज को उसका वास्तविक हक देंगे।

दूसरी तरफ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का इंडिया गठबंधन भी एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। यद्यपि अखिलेश यादव और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने बार-बार यह दोहराया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव दोनों दल मिलकर लड़ेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर सीटों के बंटवारे और प्रादेशिक नेतृत्व को लेकर दोनों दलों के स्थानीय नेताओं के बीच महत्वाकांक्षाओं का टकराव साफ दिखाई देता है। कांग्रेस जहां लोकसभा चुनाव के उत्साह के बाद उत्तर प्रदेश में अपने पुराने गौरव को हासिल करने के लिए अधिक सीटों की मांग कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखते हुए कांग्रेस को सीमित सीटों पर समेटने की रणनीति बना रही है। इसके अतिरिक्त, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती की खामोशी और उनकी अंदरूनी बैठकों भी इस त्रिकोणीय मुकाबले को और दिलचस्प बना रही हैं। मायावती अपने खिसकते दलित वोट बैंक को सहेजने के लिए नए सिरे से कैडर कैंप आयोजित कर रही हैं। यदि बसपा अपने पारंपरिक वोट को बचाने में सफल रहती है, तो इसका सीधा नुकसान सपा-कांग्रेस गठबंधन को उठाना पड़ सकता है, जिससे अंततः भाजपा को लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी।

सियासत के इस खेल में शह और मात के मोहरे बिखर चुके हैं। जनता शांत है, लेकिन वह हर दल की चालों को बहुत बारीकी से देख रही है। रोजगार की तलाश में भटकता युवा, महंगाई से जूझता आम नागरिक और अपने अधिकारों के प्रति सजग होता जागरियों का समूह ही अंततः यह तम करेगा कि 2027 में लखनऊ के सिंहासन पर किसका राजतिलक होगा।

विश्व साक्षरता दिवस: भारत की प्रगति में बिश्वरता है निरक्षरता

शिक्षा एक सभ्य, सक्षम व सुदृढ़ समाज की आधारशिला होती है। किसी भी देश के विकास के स्तर को उस देश की शिक्षा यानी साक्षरता के प्रतिशत से ही आंका जाता है। संस्कृत की सुक्ति है विद्यां ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम् मतलब विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है। शिक्षा के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को यानी संयुक्त राष् शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा घोषित 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। एक समाज में साक्षरता विकास का एक अच्छा संकेतक है। साक्षरता का फैलाव और प्रसार आम तौर पर आधुनिक सभ्यता जैसे कि आधुनिकीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, संचार और वाणिज्य के महत्वपूर्ण लक्षण से जुड़ा हुआ है। इस तथ्य को स्पष्ट किया जा सकता है क्योंकि



अमेरिका और कनाडा जैसे सभी विकसित देशों में निरक्षरता दर बहुत कम है, जबकि भारत, तुर्की और ईरान जैसे देशों में निरक्षरता की बहुत उच्च दर है। विश्व बैंक के अध्ययन ने एक ओर साक्षरता और उत्पादकता के बीच प्रत्यक्ष और कार्यात्मक संबंध स्थापित किए हैं तो दूसरे ओर साक्षरता पर मानव जीवन की समग्र गुणवत्ता को रेखांकित किया है।

गौरतलब है कि सात वर्ष से अधिक आयु वर्ग के एक व्यक्ति, जो किसी भी भाषा में किसी भी समझ से पढ़ और लिख सकता है, को साक्षर माना जाता है।

साक्षरता अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत चलाया था। गांधी का सपना था कि भारत में कोई निरक्षर न रहे। भारत में संसार की, सबसे अधिक अनपढ़ जनसंख्या निवास करती है। भारत में सामाजिक व्यवस्था पुरुष लिंग के लिए शिक्षा को बढ़ावा देती है जबकि महिला आबादी खासकर देश के गहरे अंदरूनी हिस्सों में स्कूलों से दूर रहती है। एक साक्षर व्यक्ति अपने सभी मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित है। सांप्रदायिकता, आतंकवाद और विकास के तहत समस्याओं से लड़ने का साक्षरता अंतिम उपाय है। जबकि निरक्षरता सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों को कम कर सकती है, इसलिए यदि हम एक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो सरकार को उचित कार्यान्वयन और बजट के साथ प्रभावी कार्यक्रमों को शुरू करने से पहले निरक्षरता की समस्या

को दूर करना चाहिए। यह विडंबना है कि आज भी हमारे नेताओं और लोगों के प्रतिनिधियों ने साक्षरता को कम से कम प्राथमिकता दी है, गरीबी उन्मूलन, भोजन, कपड़े, आश्रय, काम, स्वास्थ्य आदि इसके ऊपर है। वे विकास की प्रक्रिया के भाग के रूप में, साक्षरता को जीवन की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास के रूप में, कमजोर वर्गों में जागरूकता बनाने की प्रक्रिया के रूप में, राजनीतिक शक्ति के लोकतंत्रीकरण के भाग के रूप में, उनके कारण देने की व्यवस्था के रूप में विफल रहे हैं। वे शिशु मृत्यु दर, प्रतिरक्षण, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की भागीदारी, जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन, महिलाओं की मुक्ति, बाल विवाह, दहेज, दुल्हन जलाने जैसी सामाजिक बुराइयों जैसे मामलों में साक्षरता की प्रासंगिकता की सराहना करने में असमर्थ हैं।

आज का इतिहास

1320 गाजी मलिक दिल्ली का सुल्तान बना ।
1331 स्टीफन उरोस चतुर्थ ने खुद को सर्बिया का राजा घोषित किया ।
1449 टुमु फिले का युद्ध- मंगोलिया ने चीन के सम्राट को बंधक बनाया ।

1553 इंग्लैंड में लिंचफिल्ड शहर का निर्माण ।

1563 मैक्सीमिलियन को हंगरी का राजा चुना गया ।

1689 चीन और रूस ने नेटर्स्ज़िंस्क (निरचुल) की संधि पर हस्ताक्षर किया ।

1900 टेक्सास के गैलवेस्टोन में चक्रवाती और ज्वारीय तूफान से 6000 लोगों की मौत ।

1900 8 सितंबर को ही बोस्टन में पहले डेविस कप श्रृंखला की शुरुआत हुई थी ।

1945 आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमैन ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया था ।

1952 8 सितंबर के दिन ही जेनेवा में कॉपीराइट के लिए पहले विश्व सम्मेलन में भारत समेत 35 देशों ने हस्ताक्षर किया था ।

1962 आज ही के दिन चीन ने भारत की पूर्वी सीमा में घुसपैठ किया था ।

1988 आज माने व्यवसायी विजयपत सिंचानिया अपने माइक्रो लाइट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट से लंदन से अहमदाबाद पहुंचे ।

1991 मैसिडोनिया गणराज्य स्वतंत्र हुआ ।

1991 8 सितंबर को ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तरी और दक्षिण कोरिया की सदस्यता को मंजूरी दी थी ।

1994 आज ही के दिन चीन और ताइवान के जनप्रतिनिधियों ने सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे ।

1997 8 सितंबर के दिन ही अमेरिकी ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पैट्रिक राफ्टर को प्रथम ग्रैंड स्लैम खिताब मिला था ।

1998 2011 में निर्धारित 13वें गृह निरपेक्ष आंदोलन की मेजबानी बोलोदेश की सैंपी गयी ।

2000 आज ही के दिन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर सम्मेलन के दौरान हिंदी में भाषण देते हुए पाकिस्तान को फटकार लगाई थी ।

2002 नेपाल में माओवादियों ने 119 पुलिस कर्मियों को मार डाला ।
2003 में आज ही के दिन इस्त्रायल के प्रधानमंत्री एरियल शैरोन 4 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे ।

2006 महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में मालेगांव बम धमाके ।

2008 8 सितंबर के दिन ही प्रसिद्ध अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स ने भारतीय अरब पति लक्ष्मी मित्तल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की थी ।

पश्चिम बंगाल के दुर्गापूजा में दिखेगा सत्ता परिवर्तन का असर?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

पश्चिम बंगाल की राजनीति में दुर्गापूजा सिर्फ पांच दिनों का धार्मिक उत्सव नहीं है। यह बंगाली समाज की संस्कृति, कला, अर्थव्यवस्था, सामुदायिक जीवन और राजनीति सबको एक साथ जोड़ने वाला सबसे बड़ा सार्वजनिक मंच है। इसलिए जब राज्य में सत्ता बदलती है तो उसका असर दुर्गापूजा पर भी दिखाई देना स्वाभाविक है। इस बार यह बदलाव और महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी सत्ता संभाल रहे हैं।

इसलिए सवाल केवल इतना नहीं है कि इस बार पंडाल कैसे सजेंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा के शासन में दुर्गापूजा की पूरी राजनीतिक-सांस्कृतिक भाषा बदलने वाली है? 2026 की दुर्गापूजा 16 से 21 अक्टूबर के बीच होगी। यह पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन के बाद पहली दुर्गापूजा होगी। इस लिहाज से यह सरकार के लिए भी एक तरह की सांस्कृतिक परीक्षा है। भाजपा को एक तरफ अपने समर्थक वर्ग को यह संदेश देना है कि सत्ता परिवर्तन का असर जमीन पर दिख रहा है, तो दूसरी तरफ बंगाल

की उस सांस्कृतिक पहचान को भी स्वीकार करना है जिसमें दुर्गापूजा किसी एक राजनीतिक विचारधारा की संपत्ति नहीं है।

सबसे बड़ा बदलाव पहले ही दिखाई देने लगा है। सत्ता परिवर्तन के बाद कोलकाता के कई बड़े और चर्चित दुर्गापूजा आयोजक समितियों में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। कई समितियों में, जो पहले तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेताओं या समर्थकों के प्रभाव में मानी जाती थीं, नए पदाधिकारियों को जगह मिली है। कुछ समितियों ने अपनी कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया है।

इसका मतलब यह नहीं कि हर पंडाल भाजपा के कब्जे में चला गया है। लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल की सत्ता बदलते ही उन सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं के भीतर भी शक्ति संतुलन बदलने लगा है, जिनका राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रहा है। यही बदलाव दुर्गापूजा को लेकर भाजपा की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति हो सकता है—सरकार से ज्यादा समाज में अपनी मौजूदगी बढ़ाना। ममता बनर्जी के लंबे शासन में दुर्गापूजा सरकारी कार्यक्रमों, प्रशासनिक सहयोग और राजनीतिक जनसंपर्क का बड़ा माध्यम बन गई थी। मुख्यमंत्री खुद बड़ी संख्या में पूजा पंडालों का उद्घाटन करती थीं।



राज्य सरकार की ओर से पूजा समितियों को आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। 2025 में यह सहायता बढ़ाकर प्रति पूजा समिति 1.10 लाख रुपये तक पहुंच गई थी।

भाजपा के सत्ता में आने के बाद इस व्यवस्था में बदलाव का संकेत मिल चुका है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जून में संकेत दिया था कि सरकार सभी पूजा समितियों को एक समान आर्थिक सहायता देने की पुरानी व्यवस्था जारी रखने के बजाय जरूरत के आधार पर सहायता देने पर विचार कर रही है। बाद में सामने आई जानकारी के मुताबिक 10 लाख रुपये से कम बजट वाली लगभग 75 प्रतिशत पूजा समितियों को सहायता जारी रहने की संभावना है, जबकि अपेक्षाकृत समृद्ध समितियों को सरकारी अनुदान से बाहर किया जा सकता है। ममता सरकार ने दुर्गापूजा को

विचार

बड़े पैमाने पर सरकारी सहयोग और जनकल्याणकारी राजनीति से जोड़ा था। भाजपा सरकार इसे अधिक ‘जरूरत आधारित’ मॉडल में बदलना चाहती दिखाई दे रही है। यानी सरकार का तर्क यह हो सकता है कि गरीब या छोटे पूजा आयोजकों को मदद मिले, लेकिन करोड़ों रुपये के बजट वाले बड़े कॉरपोरेट-प्रायोजित पंडालों को सरकारी पैसे की जरूरत नहीं है।

लेकिन इसके राजनीतिक अर्थ भी हैं, क्योंकि बंगाल में पूजा समितियां केवल धार्मिक संगठन नहीं हैं। ये स्थानीय सामाजिक नेटवर्क हैं। मोहल्ले की राजनीति, क्लब संस्कृति, युवा संगठन, व्यापारिक समुदाय और स्थानीय नेताओं के बीच इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस राजनीतिक दल की इन समितियों तक ज्यादा पहुंच होती है, उसकी स्थानीय सामाजिक पकड़ भी मजबूत होती है। भाजपा इस नेटवर्क को अब नए सिरे से बनाने की कोशिश करेगी।

इसकी एक झलक पिछले साल ही दिखाई दे चुकी थी, जब भाजपा ने दुर्गापूजा के दौरान बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई थी। पार्टी कार्यकर्ताओं को पूजा पंडालों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने और

साड़ी वितरण जैसे कार्यक्रमों के जरिए संपर्क बढ़ाने को कहा गया था। इसका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक उत्सव में भाग लेना नहीं, बल्कि ‘बंगाली अस्मिता’ के सवाल पर तृणमूल के राजनीतिक नैरेटिव का मुकाबला करना भी था। अब फर्क इतना है कि तब भाजपा विपक्ष में थी और अब सत्ता में है।

भाजपा के सामने सबसे बड़ा सांस्कृतिक सवाल भी यही है कि क्या वह बंगाल की दुर्गापूजा को उत्तर भारत के धार्मिक उत्सवों की तरह देखेगी या उसकी विशिष्ट बंगाली परंपरा को उसी रूप में स्वीकार करेगी? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल की दुर्गापूजा की पहचान सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं बनी। इसमें कला है, साहित्य है, संगीत है, लोक संस्कृति है, सामाजिक समावेश है और आधुनिकता भी है। कोलकाता के पंडाल पिछले कई दशकों से देश-दुनिया के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को अपनी थीम बनाते रहे हैं।

2025 में भी यह साफ दिखाई दिया था। जहां कुछ पंडालों ने बंगाली भाषा और अस्मिता को केंद्र में रखा, वहीं भाजपा से जुड़े आयोजनों में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और राष्ट्रीय गौरव जैसे विषयों को प्रमुखता मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में

चीन के सैन्य मॉडल की राह पर पाकिस्तान!

नीरज कुमार दुबे

अब पाकिस्तान भी चीन के सैन्य मॉडल की राह पर चल पड़ा है। करीब पांच दशकों बाद पाकिस्तान ने अपने सैन्य कमांड ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वित कमान को नई दिशा देने की कोशिश की है। इस पुनर्गठन का सबसे बड़ा फायदा फोल्ड मार्शल असीम मुनीर को मिलता दिखाई दे रहा है, जिनके हाथों में पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था की ताकत पहले से कहीं अधिक केंद्रित हो सकती है। यह बदलाव केवल प्रशासनिक फेरबदल नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य शक्ति, रणनीतिक हथियारों और युद्धकालीन फैसलों को अधिक केंद्रीकृत करने की व्यापक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि नए कानूनों और संवैधानिक बदलावों के बाद पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (सीडीएफ) की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। असीम मुनीर पहले से सेना प्रमुख हैं और अब तीनों सेनाओं यानि थल सेना, नौसेना और वायुसेना, के बीच समन्वित कमान के केंद्र में भी हैं। पुरानी व्यवस्था में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पद तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की भूमिका निभाता था, लेकिन नई व्यवस्था में कमान का केंद्र और अधिक स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति के आसपास सिमत गया है। यही इस बदलाव का सबसे बड़ा संदेश है कि पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था में सेना अब केवल सबसे ताकतवर संस्था नहीं रहना चाहती, बल्कि अपनी ताकत को कानून और संस्थागत ढांचे के जरिए स्थायी रूप देना चाहती है। रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान ने अपने रणनीतिक सैन्य ढांचे को भी नए सिरे से संगठित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जैसी व्यवस्था के जरिए परमाणु हथियारों, मिसाइल क्षमताओं और अन्य रणनीतिक संसाधनों की कमान को अधिक केंद्रीकृत करने की कोशिश की जा रही है। इससे पाकिस्तान के सामरिक निर्णयों में सेना की भूमिका और मजबूत होती दिखाई देती है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान का यह नया मॉडल चीन की सैन्य संरचना से भी प्रभावित माना जा रहा है। सेना, नौसेना, वायुसेना, मिसाइल और रणनीतिक क्षमताओं को एकीकृत कमान के तहत लाने की सोच का उद्देश्य युद्ध या संकट की स्थिति में तेज फैसले और संयुक्त सैन्य कार्रवाई बताया जा रहा है। पाकिस्तान लंबे

समय से अपनी सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण में चीन के साथ सहयोग बढ़ाता रहा है और नया कमांड मॉडल भी उसी व्यापक रणनीतिक दिशा का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन भारत के लिए सवाल यह है कि क्या असीम मुनीर के हाथों में अधिक शक्ति आने से खतरा बढ़ जाएगा? देखा जाए तो इसका जवाब केवल हां या नहीं में नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान की सैन्य संरचना में केंद्रीकरण निश्चित रूप से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक घटनाक्रम है। एकीकृत कमान से पाकिस्तान सीमित युद्ध, मिसाइल संचालन और बहु-क्षेत्रीय सैन्य अभियानों में बेहतर समन्वय की कोशिश कर सकता है। खासतौर पर भारत की पश्चिमी सीमा के संदर्भ में पाकिस्तान अपनी सैन्य तैयारी को अधिक संगठित करने का प्रयास करेगा। लेकिन पाकिस्तान को यह ध्रम पालने की जरूरत नहीं है कि कमांड स्ट्रक्चर बदलने से जमीन पर उसकी सामरिक वास्तविकता भी बदल जाएगी। भारत के सामने पाकिस्तान की चुनौती केवल हथियारों या पदों की नहीं है। भारत के पास कहीं अधिक व्यापक सैन्य, आर्थिक और तकनीकी क्षमता है। आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों और मिसाइलों की संख्या से तय नहीं होते। अर्थव्यवस्था, रक्षा उत्पादन, तकनीक, खुफिया क्षमता, साइबर शक्ति, अंतरिक्ष क्षमता और राजनीतिक स्थिरता, ये सभी युद्ध शक्ति के महत्वपूर्ण आधार हैं। यहीं पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। एक तरफ पाकिस्तान सैन्य कमान को मजबूत और केंद्रीकृत कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी अर्थव्यवस्था लगातार दबाव में है। देश राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझता रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा समस्याएं अलग हैं। ऐसे में केवल सेना प्रमुख के हाथों में अधिक अधिकार देने से पाकिस्तान की मूल समस्याएं समाप्त नहीं हो जाएंगी। यहां एक सवाल यह भी है कि क्या सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण पाकिस्तान की संस्थाओं को और कमजोर करेगा? देखा जाए तो पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि वहां सेना और निर्वाचित सरकार के बीच शक्ति संतुलन हमेशा विवाद का विषय रहा है। अब यदि सैन्य कमान, रणनीतिक हथियारों और तीनों सेनाओं के समन्वय की शक्ति एक ही शीर्ष सैन्य नेतृत्व के इर्द-गिर्द केंद्रित होती है, तो नागरिक नियंत्रण को लेकर सवाल और गहरे होंगे।

जेपी आंदोलन से लेकर आज के जंतर–मंतर तक

रामचंद्र गुहा

जुलाई की शुरुआत में, जब जंतर–मंतर पर छात्रों का विरोध–प्रदर्शन आकार ले रहा था, तब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा उन शुरुआती राजनेताओं में से थीं, जिन्होंने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर छात्रों का समर्थन किया। प्रदर्शन के तीन सप्ताह बाद, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तब मोइत्रा ने युवा पीढ़ी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने ‘भारतीय लोकतंत्र को बचाने’ का काम किया है और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जिस काम को पिछले 12 साल में विपक्षी दल नहीं कर पाए थे, वह युवाओं ने कर दिखाया।

यह कहना जल्दबाजी होगी कि छात्रों के इस आंदोलन से पैदा हुई ऊर्जा और गति आगे कायम रह पाएगी या नहीं और क्या इससे संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के वादों को व्यापक रूप से फिर से जीवित करने का रास्ता खुलेगा। इतिहासकार ज्योतिषी नहीं होते। इसलिए भविष्यवाणी करने के बजाय मैं यहां अतीत की ओर देखा चाहूंगा, जब भारत के छात्रों ने राजनीति और सार्वजनिक जीवन पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की थी।

ऐसा पहला महत्वपूर्ण अवसर आज से लगभग 120 वर्ष पहले बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान आया था। इस आंदोलन पर लिखी अपनी पुस्तक में इतिहासकार सुमित सरकार ने बताया है कि हर जिले के छात्र पढ़ने के लिए कोलकाता (तब कलकत्ता) आते थे और संभवतः उन्हीं के माध्यम से यह आंदोलन सबसे पहले कलकत्ता से निकलकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा। आंदोलन के प्रमुख नेता भले ही स्थापित पेशेवर और जमींदार वर्गों से आते थे, लेकिन सुमित सरकार के अनुसार, आंदोलन के स्वयंसेवक मुख्यतः छात्र समुदाय से ही थे और उनमें से कई को उम्र बेहद कम थी। इसके बाद के वर्षों में भी छात्रों ने महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में ब्रिटिश



औपनिवेशिक शासन के खिलाफ चलाए गए विभिन्न आंदोलनों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़ी संख्या में पुरुष छात्रों ने हिस्सा लिया और वह जेल भी गए। ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन की एक खासियत युवा महिलाओं की सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका थी। बंबई विश्वविद्यालय की छात्रा उषा मेहता जिन्होंने भूमिगत ‘कांग्रेस रेडियो’ के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उषा ठक्कर की एक उत्कृष्ट पुस्तक में दर्ज है। लेकिन ऐसे कुछ और उल्लेखनीय उदाहरण भी थे, जिनके बारे में आज अपेक्षाकृत कम जानकारी है।

मुझे अभिलेखागार में ‘कर्नाटक इन रिवोल्ट’ शीर्षक से एक फाइल मिली। इसमें बताया गया है कि भारत के इस हिस्से में आंदोलन की ‘सबसे असाधारण विशेषता’ छात्र समुदाय की प्रतिक्रिया थी। छात्रों ने बेलगामा, गडग, बंगलूरु, मैसूर, बीजापुर, बेल्गारी, तिसरी और अन्य स्थानों पर बहिष्कार और हड़तालें आयोजित कीं।

23 अक्टूबर, 1942 को धारवाड़ की दो छात्राएं, मिस रोसेलिकर और मिस गुलवाड़ी, जिला अदालत में दाखिल हुईं। उन्होंने वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया, उपस्थित जिला जज से कहा कि उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जाता है, पचै बाटे और फिर वहां से गायब हो गईं। काश! उनके जीवन की आगे की कहानी इतिहास के इन दस्तावेजों में कहीं दर्ज मिलती। 1968 में अमेरिकी विद्वान फिलिप जी.

विनीत नारायण

जब से ‘जेन-कॉ’ ने जंतर मंतर पर नीट पेपर लोक के खिलाफ सफल धरने का आयोजन किया है, तब से पूरे देश के विद्यार्थियों में अभूतपूर्व नवचेतना का उदय हुआ है। आज देश भर के ग्रामीण अंचलों के खस्ताहाल सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी अपने स्कूलों की अव्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाने लगे हैं। उनमें स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछने की हिम्मत आ गई है। प्रसन्नता तो इस बात की है कि अब ऐसी चेतना प्राथमिक पाठशालाओं के बच्चों तक में पैदा हो गई है। वे अपने स्कूल की जर्जर या नदारद इमारत, शौचालयों का अभाव, शिक्षकों की संख्या में भारी कमी, स्कूल से मिलने वाले भोजन की खराब क्वालिटी, स्कूल तक पहुंचने वाले मार्गों की दुर्दशा, जैसे गंभीर मुद्दों पर खुलकर और संगठित होकर सवाल पूछने लगे हैं। राजस्थान के एक माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने तो विद्यालय के गेट पर ताला ही जड़ दिया और धरने पर बैठ गईं। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, स्कूल का ताला नहीं खुलेगा। देश भर में पनप रही इस नई प्रवृत्ति से प्रशासन और सत्तारूढ़ दल हक्के–बक्के रह गए हैं। उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा। सोशल मीडिया पर ऐसे दर्जनों वीडियो रोज वायरल हो रहे हैं, जिनमें ऐसे घटनाक्रम प्रमुखता से दिखाए जा रहे हैं। सबसे रोचक बात यह है कि इस तरह विरोध के स्वर उठाने वाले छात्र किसी राजनीतिक दल के बहकावे में आकर ये कदम नहीं उठा रहे। राजनीतिक दल और उनके कार्यकर्ता तो खुद इस नई परिस्थिति से बेचैन हैं क्योंकि आज तक जनता और शासन के बीच बिचौलिए की उनकी आत्मघोषित भूमिका अब निरर्थक होती जा रही है। यही हाल मीडिया का भी है। जो मीडिया सरकारों की चाटुकारिता या उनका प्रचारक बन कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर रहा था, वह अचानक यह महसूस कर रहा है कि आम जनता की दृष्टि में अब उनकी कोई अहमियत नहीं बची। एक और रोचक तथ्य यह है कि ऐसी जागृति केवल भाजपा शासित राज्यों में आई हो, यह बात नहीं है। जिन राज्यों में कांग्रेस या अन्य दलों की

‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम वाले पंडाल का उद्घाटन किया था और उसी मौके पर उन्होंने ‘सोनार बांग्ला’ के लिए भाजपा सरकार की बात भी की थी। यानी पंडाल अब राजनीतिक संदेश देने का माध्यम भी बन चुके हैं।

संभावना है कि भाजपा समर्थित या भाजपा के करीब माने जाने वाले पूजा आयोजनों में सनातन परंपरा, बंगाल का धार्मिक इतिहास, हिंदू सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय सेना, राष्ट्रीय गौरव और बंगाली हिंदू पहचान जैसे विषय ज्यादा दिखाई दें। लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि सरकार सभी पंडालों को ऐसी थीम अपनाने के लिए कहेगी। ऐसा कोई व्यापक सरकारी निर्देश सामने नहीं आया है।

दरअसल, भाजपा के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है यदि सरकार दुर्गापूजा को बहुत अधिक राजनीतिक या धार्मिक रंग देने की कोशिश करती है तो तृणमूल कांग्रेस को तुरंत यह कहने का मौका मिल सकता है कि भाजपा बंगाल की उदार और समावेशी संस्कृति को बदलना चाहती है। दूसरी तरफ यदि भाजपा पूरी तरह उलटस्थ रहती है तो उसके अपने समर्थक वर्ग को लग सकता है कि सत्ता में आने के बाद पार्टी ने सांस्कृतिक मुद्दों पर अपनी वैचारिक धार कमजोर कर दी।

ऑल्टबैक ने ‘टर्मोइल एंड ट्रांजिशन = हायर एजुकेशन एंड स्टूडेंट पॉलिटिक्स इन इंडिया’ नाम से एक पुस्तक का संपादन किया। किताब की भूमिका में ऑल्टबैक ने लिखा कि स्वतंत्रता संग्राम में छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन 1947 के बाद अधिकांश छात्र आंदोलन सीधे तौर पर राजनीतिक नहीं रहे, बल्कि वे गैर–वैचारिक मुद्दों से जुड़े रहे। पुस्तक में 1960 के दशक के छात्र आंदोलनों से जुड़े कॉलेजों की बड़ी हुई फीस और छात्रावासों की खराब सुविधाओं जैसे मुद्दे तो थे ही, साथ ही संगीत और रंगमंच जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े सवाल भी शामिल थे। लेकिन इस पुस्तक के प्रकाशित होने के एक साल के भीतर ही छात्रों ने फिर से राजनीति में सक्रिय वापसी कर ली। 1969 में शुरू हुए अलग तेलंगाना राज्य के आंदोलन में छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद भारत में उभरे तीन प्रमुख क्षेत्रीय आंदोलनों में छात्रों की भूमिका विशेष रूप से दिखाई देती है। इनमें पहला तेलंगाना आंदोलन था। इसके अलावा 1970 के दशक के आखिर और 1980 के दशक की शुरुआत का असम आंदोलन तथा 2000 के दशक का उत्तराखंड आंदोलन भी छात्र सक्रियता से गहराई से जुड़े रहे।

असम आंदोलन के बारे में इतिहासकार अरूपज्योति सैकिया लिखते हैं कि यह आंदोलन मुख्यतः छात्र नेताओं के हाथों में था। उनके अनुसार, इन नेताओं के आदर्शवाद ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रेरित किया। जब वे जोशीले भाषण देते थे, तो महिलाएं और पुरुष, दोनों ही बड़ी तल्लीनता से उनकी बातें सुनते थे। अल असम स्टूडेंट्स यूनियन के आंदोलन ने आगे चलकर असम गण परिषद में अपनी पुस्तक ‘प्रोटेस्ट मूवमेंट्स इन टू इंडियन स्टेट्स’ में गुजरात और बिहार में हुए इन विरोध प्रदर्शनों के बारे में लिखा है। दोनों ही राज्यों में छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जनता की जागरूकता लोकतंत्र के लिए जरूरी

सरकारें हैं, वहां के छात्र भी शिक्षा व्यवस्था की खामियों को लेकर अब मुखर हो गए हैं। कुछ पत्रकार तो हमेशा अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाते आए हैं। इस माहौल से उत्साहित हो कर जब उन्होंने कुछ राज्यों में विद्यालयों की दुर्दशा पर रिपोर्टेज की तो उससे घबराकर वहां के मुख्यमंत्रियों ने ऐसे पत्रकारों के विरुद्ध पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई शुरू करवा दी। मजे की बात यह है कि ऐसा करने वालों में वे मुख्यमंत्री भी हैं, जो दिन–रात सैंकड़ों करोड़ रुपए अपने प्रचार–प्रसार का बजट खर्च करके अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटते हैं। दरअसल ऐसे मुख्यमंत्री, चाहे किसी भी दल के क्यों न हों, इस मुगालते में थे कि उनका आक्रामक प्रचार, उनके शासन की कमजोरियों को ढक लेगा। जब मीडिया ही मैनेज हो गया तो उनकी सरकारों की कमजोरियां आम जनता तक कौन पहुंचाएगा? लेकिन अब पासा पलट गया। मीडिया तो मैनेज हो गया लेकिन रिपोर्टेज का फायदा उठा कर अब हर छात्र एक टिपोटर बन चुका है। वह एक स्मार्टफोन से जमीनी हकीकत दिखाकर, सरकार के झूठे दावों की पोल खोल रहा है। यह तो एक तरह का ऐसा सैलाब है, जिसे काबू कर पाना अब किसी भी दल की सरकार के लिए नामुमकिन होगा। दो–चार पत्रकारों पर तो दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है लेकिन जब विद्यालयों के सैंकड़ों छात्र हकीकत बयान करने लगे तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर किसी मूख् नेता ने अहंकारवाण ऐसा करने का दुसाहस किया तो वह ठोड़ ठोड़ बैंक की खो देगा। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य को लेकर हर माता–पिता चिंतित रहता है। जब वे देखेंगे कि उनके बच्चों को स्कूलों में बुनियादी सुविधा मिलना तो दूर उल्टा उसके विरुद्ध आवाज उठाने पर पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई को झेलना पड़ रहा है, तो उनका पारा भी सातवें आसमान पर चढ़ेगा। ऐसे हालातों को काबू कर पाना किसी भी मंत्री या सरकार के लिए असंभव होगा। यह तो एक शुरुआत है, जो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसका दायरा अब और बढ़ना चाहिए। हर आम नागरिक को अपने परिवेश पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।

सीआरपीएफ ने बरामद किए 14 नक्सल डंप, भारी मात्रा में ईआईडी और हथियार जब्त

बीजापुर। नक्सल विरोधी अभियान के तहत 199वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने बड़ी सफलता हासिल की है। 5 सितंबर 2026 को सीआरपीएफ की 199वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने एड़ी, हरीं, नयापारा एवं सरपंचपारा पीडिया व कुआपगुड़ा गांवों के जंगल क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाकर नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 14 नक्सल डंप बरामद किए हैं।

प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर कमांडेंट-199 वाहिनी आनंद कुमार के मार्गदर्शन एवं उप कमांडेंट दर्शन यादव की देखरेख में बी 199 कंपनी और यंग प्लाटून के जवानों ने अभियान चलाया। बी 199 कंपनी कमांडर अजित कुमार डेका तथा एफ 199 कंपनी निरीक्षक नीरज कुमार के नेतृत्व में जवानों ने जंगल क्षेत्र की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया।

तलाशी के दौरान जवानों को नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से छिपाकर रखी गई सामग्री मिली। बरामद सामान में 7 रायफल, जिसमें 303 बोल्ट एक्शन रायफल 1, भरमार रायफल 5 और 12



बोर देशी रायफल 1, आठ डेटोनेटर, कोडेक्स वायर, 10 द्रुध्द, बिना बैटरी का एक वायरलेस सेट, चार प्लास्टिक कंटेनर और तीन बड़े स्टील कंटेनर शामिल हैं। इसके अलावा द्रुध्द बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिक सामग्री और नक्सलियों के कपड़े समेत कुल 99 प्रकार की वस्तुएं बरामद की गई हैं।

अभियान के दौरान जवानों ने अत्यंत सतर्कता बरतते हुए इलाके की घेराबंदी और चरणबद्ध तरीके से सर्च ऑपरेशन किया। बरामद सामग्री नक्सलियों द्वारा भविष्य में सुरक्षा बलों को नुकसान

पहुंचाने के उद्देश्य से छिपाकर रखी गई थी। उल्लेखनीय है कि एड़ी, हरीं तथा पीडिया कुआपगुड़ा और आसपास का क्षेत्र पूर्व में नक्सली गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील रहा है। छत्रस्त्र की 199वीं वाहिनी द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियानों के परिणामस्वरूप क्षेत्र में नक्सल प्रभाव कम हुआ है और ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

199वीं वाहिनी के कमांडेंट आनंद कुमार ने कहा कि बल आम नागरिकों की सुरक्षा, क्षेत्र में शांति एवं विकास

सुकमा के जंगल में नक्सली डंप, भरमार बंदूक से लेकर वायरलेस सेट और विस्फोटक सामग्री बरामद

सुकमा। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। चिंतलनार थाना क्षेत्र के चित्राबोड़केल के पहाड़ी-जंगल इलाके में सर्चिंग के दौरान जवानों ने नक्सलियों द्वारा पहले से छिपाकर रखे गए डंप का पता लगाया। यहां से हथियार, विस्फोटक, गोला-बारूद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य नक्सली उपयोगी सामग्री बरामद की गई है।

सुकमा पुलिस के मुताबिक, 5 सितंबर को मिले इंटेलिजेंस के आधार

सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 199वीं वाहिनी द्वारा भविष्य में भी आसूचना आधारित अभियानों की और प्रभावी तरीके से संचालित किया जाएगा तथा क्षेत्र को पूर्णतः नक्सलमुक्त बनाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।



पर कैंप रायगुडेम से 223वीं वाहिनी सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल

सामग्री भी मिली है। सुरक्षा बलों को डंप से नक्सली साहित्य, झंडा, यूनिफॉर्म, तीर-कमान, लोहे की स्पाइक और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि बरामद सामग्री

की संयुक्त टीम को चित्राबोड़केल के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन

को सुरक्षित कब्जे में लेकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

अधिकारियों के मुताबिक, नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत जंगलों और दुर्गम इलाकों में पहले से छिपाकर रखे

और सर्चिंग के लिए रवाना किया गया था। सर्चिंग के दौरान संदिग्ध डंप मिला, जिसके बाद इलाके की सघन तलाशी ली गई।

बरामद सामग्री में एक भरमार बंदूक, बीजीएल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली 57 पाइप, तीन आईईडी कंटेनर, दो वायरलेस सेट, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर समेत अन्य डेटोनेटर, करीब एक किलो गन पाउडर और तीन किलो यूरिया शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में बैटरियां, इलेक्ट्रिक तार, चार्जर, रेडियो सेट, सॉफ्ट बोर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक

गए हथियारों और विस्फोटक डम्प की तलाश लगातार जारी है। सुकमा पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास का माहौल कायम करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

आंगनबाड़ी भवन निर्माण में मिली अनियमितताएं, सब इंजीनियर पर एफआईआर और निलंबन के दिए निर्देश

कोरबा। खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सख्त रख अपनाया है। निरीक्षण के दौरान उन्हें आंगनबाड़ी और स्कूल भवन के निर्माण में गंभीर अनियमितताएं मिलीं। कहीं तय मानक से कम मोटाई का सरिया लगाया जा रहा था, तो कहीं निर्धारित मापदंड के अनुरूप टाइल्स नहीं मिलीं। गड़बड़ी सामने आने पर कलेक्टर ने मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने जनपद पंचायत कटघोरा के ग्राम जेंजरा और सलोरा में डीएमएफ मद से बन रहे आंगनबाड़ी, स्कूल और पीडीएस भवनों का निरीक्षण किया। जेंजरा के निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन में उन्हें स्लैब में लगाए जा रहे सरिया की गुणवत्ता और मोटाई पर संदेह हुआ। उन्होंने मौके पर ही सीढ़ी मंगवाकर सब इंजीनियर से सरिया का जांच कराई। जांच में 8 एमएम सरिया लगाने की जानकारी के बावजूद कई जगह 6 एमएम सरिया पाया गया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कलेक्टर ने पंचायता तैयार कर एफआईआर दर्ज करने और सब



इंजीनियर को निलंबित करने के निर्देश दिए।

जेंजरा में ही स्कूल भवन के फर्श पर लगी टाइल्स निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं मिलीं। कलेक्टर ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम सलोरा में पीडीएस भवन की प्लिंथ जमीन के स्तर से काफी नीचे मिली, जिस पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और जांच के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि डीएस्एफ राशि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए है। इसमें लापरवाही पर अधिकारियों और एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटघोरा में आदिवासी विकास विभाग द्वारा बन रहे स्कूल भवन का निरीक्षण किया। देरी पर नाराजगी जताते हुए अक्टूबर तक निर्माण पूरा करने

को कहा। उन्होंने जेंजरा के जर्जर आंगनबाड़ी भवन को भी देखा।

कलेक्टर ने जनपद में लंबित फाइलों और उपयोगिता प्रमाण पत्रों पर भी सख्ती दिखाई। कहा कि पूर्ण कार्यों के प्रमाण पत्र अनावश्यक रूप से न रोके जाएं, इससे भुगतान और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। जनपद सीईओ को कर्मचारियों के कार्यों की जांच और फाइलें लटकने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। जेंजरा के उपयोगिता प्रमाण पत्र में देरी पर संबंधित बाबू का वेतन रोकने को कहा।

कलेक्टर ने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, एसडीएम विपिन दुबे, अपर कलेक्टर माधुरी सोम ठाकुर सहित अधिकारी मौजूद रहे।

कृष्ण प्रकटोत्सव पर प्रदेशभर के वरिष्ठ पत्रकार सम्मानित

दुर्ग। श्री श्यामा श्याम धाम ट्रस्ट उमरपोटी, दुर्ग द्वारा कृष्ण प्रकटोत्सव के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदेशभर से पहुंचे वरिष्ठ पत्रकारों को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारिता के साथ समाजसेवा और बाल वीरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मान प्रदान किया गया ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं राधा-कृष्ण मंदिर के प्रमुख सेवादार नंद कुमार कश्यप तथा विधायक ललित चंदाकर ने सम्मानित पत्रकारों को सम्मान पत्र एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय पत्रकारों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

इन पत्रकारों का हुआ सम्मान
उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रशांत शर्मा, मंजूषा शर्मा, प्रकाश शर्मा,विवेन्द्र शर्मा



श्यामा श्याम धाम ट्रस्ट ने पत्रकारिता, समाजसेवा और बाल वीरता को किया सम्मानित

ब्रजेश चौबे, राम अवतार तिवारी, अरुण मिश्रा (दुर्ग), अनिल गुप्ता (भिलाई), मोहन तिवारी, देवीलाल साहु (दुर्ग), अमृता शर्मा, संदीप पुराणिक एवं हाजी गौस मोहम्मद को सम्मानित किया गया।

समाजसेवी राजेन्द्र निगम सम्मानित
समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए राजेन्द्र कुमार निगम, अध्यक्ष

कुलदीप निगम वृद्धाश्रम एवं संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद, रायपुर को सम्मान प्रदान किया गया। समाजसेवा के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की गई।

बाल वीरता के लिए ओम उपाध्याय को विशेष सम्मान
समारोह में भिलाई निवासी बहादुर

अकलतरा में रहवासियों ने किया चक्काजाम, सड़क और ड्रेनेज की मांग

जांजगीर चांपा। आपने स्थानीय स्तर पर मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रदर्शन तो कई तरह के देखे होंगे लेकिन आज जो हम प्रदर्शन हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो सच में अनोखा है। ये प्रदर्शन हुआ अकलतरा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 11 में,जहां सड़क और नाली की मांग लंबे समय से की जा रही थी लेकिन जब काम नहीं हुआ तो रहवासियों ने ऐसा कुछ किया कि घंटे भर में प्रशासन दरवाजे पर था,और उनकी मांगों को पूरा करने का लिखित में आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया गया। अकलतरा के वार्ड क्रमांक 11 के लोग नाली निर्माण और गली की सड़क बनवाने की मांग कर रहे थे लेकिन बारिश



से पहले की गई मांग बारिश के दौरान भी पूरी नहीं हुई जिसके विरोध में रहवासियों ने सड़क में जमे गंदे पानी में उतरकर पार्षद के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने ना सिर्फ गंदे पानी से स्नान किया,बल्कि उसी में बैठकर

नाश्ता भी किया। इस प्रदर्शन के बाद रहवासियों ने चक्काजाम किया।चक्काजाम के कारण अधिकारी मौके पर पहुंचे और रहवासियों को जल्द से जल्द सड़क और नाली बनवाने का आश्वासन लिखित में दिया।

वार्डवासी ने कहा वर्षों से नाली निर्माण नहीं होने और सड़क निर्माण नहीं होने से नाली का पानी गली में भरा हुआ है,जो घरों में घुस रहा है। ऐसे में वार्डवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कीड़े और मच्छर घरों में घुस रहे हैं।अब तो जहरीले सांप भी घरों में घुसने लगे हैं। जिससे डेंगू मलेरिया, हैजा जैसी गंभीर होने का डर सता रहा है।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

500 लोगों से धोखाधड़ी, अंतागढ़ पुलिस के शिकंजे में 2 आरोपी

कांकेर। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भानुप्रतापपुर आकाश श्रीश्रीमाल ने 70 करोड़ की ठगी का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज कंपनी के संचालकों ने लोगों को कंपनी में पैसा निवेश करने पर 5 प्रतिशत ब्याज/कमीशन देने और करीब डेढ़ साल में रकम दोगुनी करने का लालच दिया। उनके झांसे में कई लोग आ गए। आरोपियों ने कांकेर, दत्तेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर समेत अन्य क्षेत्रों के लोगों को इस योजना का झांसा देकर निवेश कराया। आरोपियों ने सरकारी कर्मचारियों समेत अन्य लोगों को अलग-अलग बैंकों से लोन लेने के लिए प्रेरित किया और लोन की पूरी राशि कंपनी में निवेश कराई। शुरुआत में लाभ के रूप में कुछ किश्तों का भुगतान कर निवेशकों का विश्वास जीता गया। लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया गया। इसके बाद आरोपी लोगों की जमा राशि लेकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई।

अवैध खनिज परिवहन एवं भंडारण पर कार्रवाई, दो हाईवा जब्त

मोहला। कलेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम के निर्देशन में जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बिना वैध दस्तावेज के खनिज परिवहन करते पाए जाने पर दो हाईवा वाहनों को जब्त किया गया है। खनिज विभाग की जांच में एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 21 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 71 के उल्लंघन का मामला पाया गया। कार्रवाई के दौरान हाईवा क्रमांक सीजी 04 पीएफ 9320 एवं सीजी 09 जेएल 9808 को जब्त कर आगामी कार्रवाई तक पुलिस अभिरक्षा में रखने के लिए संबंधित थाना प्रभारी लिखित में आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया गया है। इसी प्रकार तहसील अंबागढ़ चौकी के ग्राम मोंगरा में अवैध रूप से भंडारित लगभग 80 माजदा रेत को भी जब्त किया गया है। मामले में नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। खनिज विभाग द्वारा जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामलों पर सतत निगरानी रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

जीपीएम में जल उत्सव के साथ हुआ हट घर जल प्रमाणीकरण

गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही। विकासखंड गौरैला के ग्राम गिखर में जल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्राम में ‘हर घर जल’ प्रमाणीकरण किया। साथ ही जल अर्पण दिवस के अंतर्गत नल-जल योजना का ग्राम पंचायत को विधिवत हस्तांतरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत सदस्य द्वारा नल-जल योजना ग्रांप को हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर ग्रामीणों को जल के महत्व, जल के सदुपयोग एवं संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में नल कनेक्शनों को फ्लों की माला पहनाकर जल के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का संदेश दिया गया जिंप सदस्य प्रतिनिधि बृजलाल राठौर ने कहा कि हर घर तक नल से स्वच्छ जल की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन इस सुविधा को निरंतर बनाए रखना ग्रामवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने ग्रामीणों से जल स्रोतों के आसपास सोखा गट्टे बनाने, जल स्रोतों की साफ-सफाई बनाए रखने तथा नल-जल योजना के उचित रख-रखाव में सक्रिय भागीदारी निभाने को अपील की।

कोटाडोल पुलिया को अस्थायी मरम्मत कार्य पूर्ण

एमसीबी। कलेक्टर सुश्री सतन देवी जांगड़े के निर्देशानुसार भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त कोटाडोल पुलिया को अस्थायी मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद आज सोमवार से आवागमन के लिए खोल दिया गया है। यह पुलिया कोटाडोल से खिरकी के मध्य मुख्य मार्ग पर स्थित है और इसके खुलने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा। भारी वर्षा के कारण पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के बाद पीएमजेसीवाय द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सात दिवस के भीतर अस्थायी मरम्मत कार्य पूर्ण किया गया। हालांकि, पुलिया की सुरक्षा एवं संरचनात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिलहाल आवागमन पर दो महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू रहेंगे। एक समय में पुलिया से केवल एक चारपाहिया वाहन को ही गुजरने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के लोडेंड ट्रक का पुलिया से आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने वाहन चालकों से निर्धारित प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करने तथा पुलिया से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।

एनएच-130 क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण पर अस्थायी प्रतिबंध

अंबिकापुर। राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के उन्नयन एवं प्रस्तावित 4-लेन निर्माण कार्य के लिए जिला सरगुजा अंतर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। तहसील लखनपुर अंतर्गत ग्राम लखनपुर, शिवपुर एवं भरतपुर से होकर गुजरने वाले प्रस्तावित 4-लेन एन.एच.-130 के रिअलाइन्मेंट भाग में आने वाली मध्य रेखा के दोनों ओर 50-50 मीटर तक प्रभावित सम्पूर्ण भूमि के ऋय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन एवं भूमि व्यपवर्तन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने से लेकर भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य प्रभावित भूमि के स्वाधिन एवं हिस्सेदारी में अनावश्यक परिवर्तन को रोकना तथा सुआवजा निर्धारण एवं भूमि अर्जन की प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-130 परियोजना के अंतर्गत पूर्व में भी प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के ऋय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन एवं व्यपवर्तन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

पेंड्रा के छात्र ने मैदान बनाने के लिए तैयार किया रोबोट

जीपीएम। छत्तीसगढ़ के गौरैला-पेंड्रा-मरवाही जिले के एक होनहार छात्र पवित्र सराफ मानस ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (सेजेस), पेंड्रा में पढ़ने वाले पवित्र का चयन देश की प्रतिष्ठित इंस्पायर-मानक (INSPIRE-MANAK) प्रतियोगिता के लिए हुआ है. वे अपने अनोखे आविष्कार GroundMaster Pro के साथ राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिले के इतिहास में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने वाले वे पहले छात्र हैं, जिन्होंने यह सावित कर दिया कि हुनर किसी बड़े शहर का मोहताज नहीं होता। तकनीक, गेम डेवलपमेंट और गेम डिजाइनिंग में विशेष रुचि रखने वाले पवित्र ने आउटडोर गेम्स को तकनीक से जोड़ने की सोच के साथ



GroundMaster Pro तैयार किया है। दअसल, ग्राउंड में जो चूना से लाइनिंग की जाती है वो सही से नहीं होती, उसके लिए पवित्र ने एक मॉडल बनाया, रोबोट तैयार किया है। रोबोट को मोबाइल से कनेक्ट किया है और उसमें स्पे डालने के बाद सिर्फ ग्राउंड की दिशा और माप बताती होती है। इसके बाद वह रोबोट

सिस्टोमेटिक ग्राउंड बनाएगा। यह हमारे जिला स्तर पर चयन हुआ, फिर संभाग और आगे राज्य स्तर पर चयन हुआ है। आगे अब वो दिल्ली जाएगा, हम चाहते हैं अब उसका चयन वहां भी हो, कलेक्टर ने भी आशीर्वाद दिया, हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी हैं- रजनीति तिवारी ज़िला शिक्षा अधिकारी

पवित्र सराफ का सपना इससे भी बड़ा है। वे भविष्य में छत्तीसगढ़ की अपनी Gaming Universe विकसित करना चाहते हैं, जिसमें आधुनिक तकनीक और गेमिंग के साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं पहचान को भी जोड़ा जा सके। पवित्र ने बताया कि उनकी इस सफलता के पीछे उनके मार्गदर्शक शिक्षक अमन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने पवित्र के विचार को प्रोजेक्ट में बदलने से लेकर उसमें लगातार सुधार और प्रतियोगिता की तैयारी तक मार्गदर्शन दिया। अमन सिंह स्वयं वर्ष 2023 में तिरुवनंतपुरम में आयोजित हड़ुहदुधशुडुडुह स्हह्रसदशुह्रह्र छशशुछशुडुडुह, डुडुडुस्स के वक्तर्शाप और स्मार्ट इंडिया हैकथॉन जैसे राष्ट्रीय मंचों पर विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके मार्गदर्शन में पिछले वर्ष भी एक छात्र राज्य स्तरीय प्रतियोगिता तक पहुंचा था।

झीरम घाटी के फैसले पर जांजगीर-चांपा कांग्रेस की प्रेसवार्ता

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में हद्द कोर्ट के फैसले को लेकर जांजगीर-चांपा जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेसवार्ता की। इस दौरान जिला कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले को अंधूरा न्याय करार दिया है। वहीं, जिला अध्यक्ष ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि झीरम घाटी घटना से जुड़ी अहम जानकारियां कांग्रेस के जिस नेता की पॉकेट में हैं, उसे उचित समय आने पर जनता के सामने लाया जाएगा। इसके साथ ही, जिला कांग्रेस कमेटी की समीक्षा बैठक में प्रदेश सह-प्रभारी विजय जांगिड़ ने पार्टी के प्रदर्शनों में आम जनता के नदारद रहने पर नाराजगी जताई है और संगठन को जनता को सीधे आंदोलनों से जोड़ने के कड़े



निर्देश दिए हैं। जांजगीर-चांपा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने विधायक ब्यास कश्यप और प्रदेश सह-प्रभारी विजय जांगिड़ की मौजूदगी में प्रेसवार्ता को संबोधित किया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन हद्द की जांच रिपोर्ट पूरी तरह अधूरी है। राजेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ने घटना में घायल

हुए कांग्रेसियों, हमले की पहली सूचना देने वाले चरमदादों और कई जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ किए बिना ही चार्जशीट पेश कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि घटना के बाद जिन नक्सलियों के नाम शुरुआत में सड्डुक में दर्ज थे, बाद में उनके नाम भी हटा दिए गए। इस अधूरे न्याय के खिलाफ कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।

आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का नवजागरण

विष्णु देव साय सरकार ने गढ़ी छत्तीसगढ़ की नई पहचान

विरासत से विकास तक : जब संस्कृति बनी सुशासन की आधारशिला

शक्तिपीठों के विकास, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, लोककलाओं के संरक्षण,
संत परंपराओं का सम्मान और यात्रा सुविधाओं के विस्तार से छत्तीसगढ़ की
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को मिली नई ऊर्जा

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

शक्तिपीठ परियोजना

आस्था को जोड़ने वाला
1000 किलोमीटर का सर्किट



माँ दत्तेश्वरी, माँ बम्लेश्वरी, माँ महामाया, माँ बागेश्वरी और माँ चंद्रहासिनी जैसे प्रमुख शक्तिस्थलों को जोड़ते हुए लगभग 1000 किलोमीटर का आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना श्रद्धा, संस्कृति और विकास का सुंदर संगम बनेगी।

मंदिरों का जीर्णोद्धार

सांस्कृतिक विरासत का
संरक्षण और संवर्धन



प्रदेशभर में प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं तथा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। इससे रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है।

श्री रामलला दर्शन योजना

श्रद्धालुओं को आस्था
से जोड़ने का सेतु



अब तक लगभग 42 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 5 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिक देश के विभिन्न तीर्थस्थलों का लाभ ले चुके हैं। यह योजना आस्था और जनसेवा का प्रभावी माध्यम है।

महाकुंभ 2025 में

छत्तीसगढ़ की
ऐतिहासिक सहभागिता



प्रयागराज में 4.5 एकड़ में बना छत्तीसगढ़ पैवेलियन 45 दिनों तक आस्था, संस्कृति और सेवा का केंद्र रहा। 50 हजार श्रद्धालुओं ने निःशुल्क आवास व भोजन की सुविधा का लाभ उठाया। राज्य की संस्कृति और पर्यटन की प्रदर्शनी ने देश-विदेश के आगंतुकों को आकर्षित किया।

“

छत्तीसगढ़ प्रभु श्रीराम का ननिहाल, माता कौशल्या की जन्मभूमि और संत परंपराओं की पावन धरती है। हमारी सरकार आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शक्तिपीठ परियोजना, रामलला दर्शन योजना, मंदिरों के जीर्णोद्धार, लोक कलाकारों के प्रोत्साहन और धार्मिक पर्यटन के विकास के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को नई ऊर्जा दे रहे हैं। हमारा विश्वास है कि कला समाज की आत्मा है और आस्था हमारी सबसे बड़ी शक्ति। विरासत के संरक्षण और जनसेवा के माध्यम से हम नए, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से सशक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रहे हैं।

”

-विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

चिन्हारी योजना

लोक संस्कृति संरक्षण
का सशक्त माध्यम



लोक कलाकारों, शिल्पकारों, गायकों और नर्तकों का पंजीयन कर व्यापक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। चयनित कलाकारों को आर्थिक सहायता, मंचों पर प्रस्तुति के अवसर और प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से नई पीढ़ी को लोक संस्कृति से जोड़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2026

कलाकारों को सम्मान व संबल



लोकनृत्य, लोकगायन, लोकनाट्य, वाद्ययंत्र, शिल्पकला, पारंपरिक पाककला सहित विभिन्न विधाओं के कलाकारों को प्रतिवर्ष 12 हजार से 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

कर्मचारियों के लिए

विपश्यना अवकाश
अनूठी पहल की शुरुआत



शासकीय कर्मचारियों में मानसिक तनाव दूर करने और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए विपश्यना (ध्यान) शिविरों में जाने के लिए विशेष सवेतन अवकाश की अनूठी पहल शुरू की गई है।

संत परंपरा और आध्यात्मिक विरासत को नया सम्मान

कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा को मिली नई पहचान



दामखेड़ा का नाम अब कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा घोषित किया गया है। प्रदेश के विभिन्न संत परंपरा केंद्रों और धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं विकास के लिए योजनाबद्ध कार्य जारी है।

भोरमदेव से कौशल्या धाम तक

धार्मिक पर्यटन का विस्तार



भोरमदेव सर्किट से स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 148 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। माता कौशल्या मंदिर, शिवरीनारायण, दंडकारण्य क्षेत्र सहित अन्य स्थलों का विकास कर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित किया जा रहा है।

गौ संवर्धन और धार्मिक संरक्षण

सामाजिक समरसता की दिशा में कदम



गौधाम योजना के माध्यम से गौधामों में आवश्यक सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

नया छत्तीसगढ़: विकास और विरासत का

संतुलित मॉडल



आस्था, संस्कृति, पर्यटन और विकास के समन्वय से छत्तीसगढ़ अपनी हजारों वर्षों पुरानी विरासत को सहेजते हुए एक समृद्ध, सुरक्षित और सांस्कृतिक रूप से सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज छत्तीसगढ़ विकास की नई इबारत नहीं लिख रहा, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी भविष्य की मजबूत नींव भी तैयार कर रहा है।

मुख्य
उपलब्धियां



शक्तिपीठ सर्किट से
आध्यात्मिक पर्यटन
को नई शक्ति



हजारों श्रद्धालुओं
को तीर्थयात्रा
की सुविधाएँ



लोक कलाकारों
का सशक्तीकरण
और सम्मान



युवाओं को छात्रवृत्ति
से उज्ज्वल भविष्य



धार्मिक धरोहरों का
संरक्षण और संवर्धन

आस्था हमारी पहचान, संस्कृति हमारी शान, सेवा हमारा संकल्प

लोकसुरों में बिखरी संस्कृति की रंगत



‘लोरिक चंदा’ से ददरिया-चंदैनी तक लोकसुरों में गुंजा छत्तीसगढ़ का लोकमन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू, लोकजीवन की सहज संवेदनाएं और पीढ़ियों से चली आ रही लोकपरंपराओं के रंगों से ‘लोकरंग पर्व’ का दूसरा दिन सराबोर रहा। मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित कार्यक्रम में ‘लोरिक चंदा’, ददरिया और चंदैनी जैसी पारंपरिक लोकविधाओं की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश की लोकप्रिय लोकगाथा ‘लोरिक चंदा’ के भावपूर्ण प्रसंग से हुई। श्री व्यासनाथ योगी एवं साथियों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से लोकगाथा की कथात्मकता, भाव और गायन परंपरा को मंच पर जीवंत कर दिया। प्रस्तुति के दौरान लोकसंगीत और पारंपरिक गायन शैली ने वातावरण को पूरी तरह छत्तीसगढ़ी रंग में रंग दिया।

इसके बाद श्री विजय साहू एवं साथियों ने ददरिया की प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ के लोकजीवन से गहरे जुड़ी ददरिया की मधुर धुनों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। वहीं श्री बरसन देशलहरे ने चंदैनी के माध्यम से प्रेम, लोकजीवन और मानवीय संवेदनाओं को सुरों में पिरोया। प्रस्तुतियों में छत्तीसगढ़ की प्राचीन जीवनशैली, लोकभावनाओं और सामाजिक सरोकारों की सहज झलक दिखाई दी।

कार्यक्रम में संस्कृति एवं पुरातत्व संचालक डॉ. संजय कन्नौजे ने कहा कि स्थानीय मंच छत्तीसगढ़ की लोकविधाओं से जुड़े कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने और प्रोत्साहन पाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी हैं।

उन्होंने कहा कि लोरिक

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

व्यापारी संघ ने शिक्षक दिवस पर प्राचार्य शर्मा का किया सम्मान



रायपुर। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर अवंती विहार व्यापारी संघ द्वारा आस्था पब्लिक स्कूल की प्राचार्य श्रीमती उमा शर्मा एवं शाला की सभी शिक्षिकाओं का शॉलडूझरीफल भेंटकर मोती की माला पहनाकर सम्मान किया , उक्त जानकारी देते हुए संघ के अध्यक्ष राजकुमार राठी ने बताया कि शिक्षक हमें न केवल ज्ञान देते हैं बल्कि शिक्षा के साथ-साथ संस्कार देकर संस्कारवान इंसान बनाकर हमें देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने का भी कार्य करते हैं। सम्मान समारोह में प्रमुख रूप से व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजकुमार राठी,महामंत्री किशोरचंद नायक, उपाध्यक्ष सुजत घोष, गोविंद शर्मा,शैलेंद्र राने,इंद्रपाल सिंह तोमर, हरीश लोकवाणी,मनीष डेगानी उपस्थित रही। इस दौरान शिक्षिका ऋतु चौधरी,शबाना कुरैशी,गायत्री निहाल,बसंती पटेल,कविता यादव, नेहा मंडल,श्वेता तिवारी,अर्चना सिंह, डिंपल विशेष रूप से उपस्थित रहे।

नए आपराधिक कानूनों को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा सख्त डैशबोर्ड के प्रत्येक मापदंड की बिंदुवार हुई समीक्षा

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने नवीन आपराधिक कानूनों के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों तथा अधिकारियों को समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को अधिक त्वरित, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाना है। इसके लिए कानून में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण की जानी चाहिए।

नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में गृह मंत्री शर्मा ने केंद्रीय



गृह मंत्रालय के नेशनल क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंटेशन डैशबोर्ड की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की बेहतर स्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की। डैशबोर्ड के प्रत्येक मापदंड की बिंदुवार समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि राज की रैंकिंग में और सुधार के लिए हर स्तर पर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप जुलाई माह से राज्य की रैंकिंग में

उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने इस प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी मापदंडों में सुधार की गति बनाए रखने के निर्देश दिए।

एफआईआर से न्यायालय तक की प्रक्रिया हो त्वरित

कार्यात्मक दक्षता के मापदंड पर सुधार के संबंध में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि

ओबीसी मोर्चा का संभाग स्तरीय सम्मेलन

सीएम साय ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

रायपुर। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रायपुर संभाग स्तरीय प्रबुद्ध जन सम्मान एवं कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओबीसी समाज की भूमिका और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम साय ने पिछली कांग्रेस सरकार पर घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ अपनी सरकार की कार्रवाई को ढाई साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओबीसी समाज की बड़ी आबादी का उल्लेख करते हुए समाज के योगदान और हुनर की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ओबीसी समाज अपने हुनर के जरिए बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में नए भारत के निर्माण की दिशा में काम हुआ है और देश लगातार आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अब देश में घुसकर मारने वाला देश बन गया है। उन्होंने दावा किया कि भारत की मजबूत कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां बंद हो गई हैं। नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर हमला

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई को ढाई साल की सरकार का सबसे बड़ा काम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य नक्सलवाद को खत्म करना है।

सीएम साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने के प्रयासों में सहयोग नहीं किया। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर भी निशाना साधा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान लगातार घोटाले होते रहे और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार करना कांग्रेस की संस्कृति रही है। नएरसन तलाशें

गौरतलब है कि इस सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू समेत भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भूपेश बघेल के बयान पर सीएम साय का पलटवार

कांग्रेस पहले खुद के भीतर झांके, पंजाब में ‘गो बैक भूपेश’ के पोस्टर का भी किया जिक्र

रायपुर। राजनीतिक दलों में प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाजपा संगठन पर सवाल उठाने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। सीएम साय ने कांग्रेस को पहले अपने भीतर झांकने की नसीहत देते हुए भूपेश बघेल के पंजाब प्रभारी रहते हुए हुए विरोध का भी जिक्र किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पहले खुद के भीतर झांकना चाहिए। कांग्रेस में प्रभारियों की नियुक्ति किस तरह हुई है, यह दुनिया जानती है। उन्होंने कहा कि जब भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाया गया था, तब वहां उनके विरोध में ‘गो बैक भूपेश’ के पोस्टर लगाए गए थे।

सीएम साय ने कहा कि पंजाब में विरोध झेलने के बाद भूपेश



बघेल को असम भेजना पड़ा। उन्होंने भूपेश बघेल के भाजपा संगठन को लेकर दिए गए बयान पर जवाब देते हुए कांग्रेस के संगठनात्मक फैसलों और अंदरूनी स्थिति पर सवाल उठाए।

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के संगठन और प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने भाजपा में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा था कि पार्टी में कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। बघेल ने भाजपा को अपनी स्थिति देखने की सलाह भी दी थी।बघेल ने कहा था

कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे किसी के सामने नहीं झुकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाईकमान किसी के सामने झुकने वाला नहीं है।भाजपा के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठाते हुए बघेल ने कहा था कि नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में दो साल लग गए और कार्यकारिणी के गठन में भी महीनों का समय लगा।उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का प्रभारी नहीं है, लेकिन भाजपा कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा कर रही है। बघेल ने तंज कसते हुए कहा था कि भाजपा में इतनी लड़ाई है कि वह एक प्रभारी तक नियुक्त नहीं कर पा रही है।

भूपेश बघेल ने भाजपा में कथित गुटबाजी का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि भाजपा को कांग्रेस की चिंता करने के बजाय अपनी स्थिति देखनी चाहिए।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले 9 को आएंगे छत्तीसगढ़

रायपुर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वे रायपुर और बिलासपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान विभागीय योजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े नियुक्ति संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रामदास आठवले सुबह 8:15 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे रायपुर स्थित स्टेट गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां अधिकारियों के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं को लेकर बैठक करेंगे। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही रायपुर नगर निगम में स्त्र/स्त्र बैकलॉग पदों पर नियुक्तियों को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा प्रस्तावित है। इसके बाद सुबह 10:45 बजे रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे।रायपुर में कार्यक्रमों के बाद रामदास आठवले सड़क मार्ग से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। बिलासपुर में वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शाम 4:30 बजे बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद गौरव सम्मान समारोह में शामिल होंगे।

प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 16 नए मरीज, रायपुर में ज्यादा संक्रमित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में आज स्वाइन फ्लू के 16 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 8 मरीज रायपुर से सामने आए हैं।इसके अलावा बिलासपुर में 3, कोरबा में 4 और रायगढ़ में 1 मरीज मिला है। नए मामलों के साथ ही जनवरी 2026 से अब तक प्रदेश में स्वाइन फ्लू से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 251 हो गई है। भौगोलिकसंदर्भ स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा स्वाइन फ्लू के मामले रायपुर जिले में सामने आए हैं। यहां कुल 108 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। नए मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और उपचार व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। प्रदेश में फिलहाल 89 स्वाइन फ्लू के मरीज एक्टिव हैं। इनमें से 22 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है, जबकि 67 मरीज अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं। राहत की बात यह है कि जनवरी से अब तक स्वाइन फ्लू से प्रदेश में एक भी मरीज की मौत दर्ज नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग संक्रमित मरीजों की निगरानी के साथ अस्पतालों में उपचार और आवश्यक व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

आप पार्टी का 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन



रायपुर। आम आदमी पार्टी ने आज 7 सितम्बर 2026 को प्रदेश प्रभारी मुकेश अहलावत जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लचर शिक्षा व्यवस्था, बर्हाल स्वास्थ्य सुविधाओं और बेरोजगारी जैसे प्रमुख जनहित के मुद्दों सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी रायपुर के नलघर चौक में शांतिपूर्ण विशाल धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।प्रदेश प्रभारी मुकेश अहलावत जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है। गरीब बच्चों के लिए सरकारी शिक्षा सरकार पूरी तरह बर्बाद कर दी है, प्रदेश शिक्षा के मामले में 34 वें नंबर पर हैं जो कि शर्मनाक है।पेंपर लोक सरकार रोक नहीं पा रही है,स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटीलेटर पर है,हर तरफ जर्जर सड़कें हैं, सड़को पर बैठे मवेशियों की जान जा रही है, बड़े बिजली बिल से जनता त्रस्त है।प्रदेश सहप्रभारी सौरभ झा ने कहा कि प्रदेश में किसान परेशान हैं,किसानों को महंगी यूरिया खाद लेना पड़ रहा है और 1 लाख रोजगार की गारंटी का वादा कर सत्ता में वाली भाजपा सरकार के राज में बेरोजगारी दर और बढ़ी है।

भाजपा के राज में ढाई साल में सड़के बढहाल हो गयी: बैज

रायपुर। पूरे प्रदेश में सड़कों की बर्हाल स्थिति के लिए भाजपा की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि सड़कों को प्रदेश के विकास की धमनी कहा जाता है, सरकार नई सड़कें तो बना नहीं पा रही, पुराने सड़कों की मरम्मत जो नियमित प्रक्रिया है, वह भी पूरी तरह बंद है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार का आधे से अधिक कार्यकाल गुजर चुका है लेकिन अभी तक केवल मंजूरी और स्वीकृति के फर्जी दावे से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। भाजपा के कुशासन में केवल भ्रष्टाचार का ही विकास हुआ है, सड़कों रखरखाव के जिम्मेदार अधिकारी मंत्रियों के परिजनों की तेरही के बंदोबस्त में रहे, आम जनता टैक्स चुकाकर भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। भाजपा के कुशासन में भ्रष्टाचार ही विकास है। शहरों से लेकर गांव सड़कों के गड्डे तालाब बन चुके, नए पुल-पुलियों के स्लैब गिर रहे। पीडलूडी मंत्री के गृह जिले मुंगेली जिले के अमर टापू धाम में करीब साढ़े चार करोड़ रुपये की लागत से बन रहे पुल का स्लैब पहली ही ढलाई में गिर गया, निर्माण गुणवत्ता और विभागीय निगरानी, और भ्रष्टाचार की कलई खुल गई है। यह सरकार केवल कमीशनखोरी में मस्त है।

समान नागरिक संहिता- प्रदेश में ड्राफ्टिंग तेज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता को व्यावहारिक, समावेशी और जन-उपयोगी बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा गठित छत्र समिति ने जन-परामर्श और विचार-विमर्श की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में समान नागरिक संहिता प्रारूप समिति द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री एम. के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्या श्रीमती ज्योति राठी सिंह के समक्ष विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण-पोषण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए कुलपति ने खुलकर अपनी राय रखी। बैठक में पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं से लेकर



आधुनिक वैधानिक सुधारों तक के कई अहम पहलुओं पर गहन मंथन हुआ।

बैठक के दौरान प्रदेश के प्रमुख शिक्षाविदों और कुलपति ने कानून निर्माण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन्हें छत्र समिति ने ड्राफ्टिंग प्रक्रिया में प्राथमिकता से शामिल करने का आश्वासन दिया है। देश के प्रतिष्ठित विधिक संस्थाओं में शामिल हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (।हह) के कुलपति प्रोफेसर विवेकानंदन ने पावर पाईंट प्रजेन्टेशन देकर

सहयोग देने के लिए हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिबद्धता जताई। एक ऐसा कानून हो जो देश के सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति या लिंग के भेदभाव के बिना विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक जैसे नियम तय करता है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना और विशेषकर महिलाओं के लिए न्याय व समानता सुनिश्चित करना है।